नई दिल्ली
गुरुवार
05 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 62
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



बिहार में ई-कैबिनेट व्यवस्था से फैसले लेने की....पेज-05

DELHIN/2014/58158

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट...पेज-06

एक नजर

पंजाब समेत सात राज्यों में 35 ठिकानों पर ईडी के छापे

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को चार अलग-अलग मामलों में सात राज्यों के 35 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामले सरकारी और संस्थागत संपत्तियों के फर्जी अधिग्रहण, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, निवेश धोखाधड़ी, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की समूह-एक मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितता और सहकारी समिति के धन के गबन से जुड़े हैं। ईडी के चंडीगढ़, भुवनेश्वर, हैदराबाद और केरल क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में यह कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने पंजाब में सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मोगा जिले में सरकारी और संस्थागत संपत्तियों के फर्जी अधिग्रहण तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754ए के निर्माण के लिए अधिग्रहित सरकारी जमीन के फर्जी मौत और उसके बदले मुआवजे की गलत तरीके से राशि जारी किए जाने से संबंधित है। पंजाब पुलिस की ओर से 16 जून 2024 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 101 के आधार पर ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। तलाशी अभियान आम आदमी पार्टी की पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष और मोगा से विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके पति डॉ. राकेश अरोड़ा, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर चलाया गया। डॉ. राकेश अरोड़ा से जुड़े नशामुक्ति अस्पताल को भी तलाशी के दायरे में शामिल किया गया है। ईडी की कार्रवाई सरकारी जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़ी है। दूसरी ओर ईडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. और उसके निदेशक अमित मंडल से जुड़ा है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन का मामला शुरू किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार इस निवेश योजना का संचालन मुख्य रूप से 'कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज' के नाम से किया जा रहा था।

पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सीएक्यूएम सख्त

नई दिल्ली,हि.स.। पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बुधवार को पंजाब के पर्यावरण एवं कृषि विभाग के सचिवों, 12 जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब तक किए गए उपायों की समीक्षा की गई और निगरानी एवं कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, बरनाला, लुधियाना, मालेरकोटला, मोगा, संगरूर और मानसा जिलों के अधिकारी शामिल हुए। आयोग ने निर्देश दिया कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई अभियान तेज किया जाए। नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। निगरानी में कमी या खेतों में आग की घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का बड़ा फैसलाः मौजूदा बैचों के सभी अग्निवीरों का स्थायी सैनिक बनने का मार्ग प्रशस्त

नई दिल्ली,एजेंसी। तीनों सेनाओं में चार वर्ष पहले अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनके सेनाओं में स्थायी सैनिक बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है जिसमें मेरिट के आधार पर स्थायी सैनिक बनाए जाने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों के अलावा बाकी बचे 75 प्रतिशत को पहले दो वर्ष का सेवा विस्तार और उसके बाद में नियमित किए जाने का मौका दिया जाएगा।

सेना इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो वर्ष के बाद स्थायी सैनिक बनने की पेशकश करेगी। इन 75 प्रतिशत सैनिकों को उनकी इच्छा तथा सेनाओं के चयन मानदंडों के आधार पर सेनाओं में स्थायी सैनिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय सेनाओं की सिफारिश पर लिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना अपने मूल रूप में जारी रहेगी। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि यह निर्णय बहुत सोच विचार के बाद अग्निवीरों के प्रशिक्षण के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन, फिटनेस और अनुशासन को देखते हुए लिया है और अब तक के सभी बैचों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करते समय स्पष्ट किया गया था कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यह निर्णय समीक्षा पर ही आधारित है। उन्होंने कहा,' इच्छुक 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के सेवा विस्तार की शुरूआत अग्निवीरों की



आकांक्षाओं और संगठनात्मक दक्षता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के मूल उद्देश्य से, विचार-विमर्शपूर्ण, तर्कसंगत एवं विस्तृत मूल्यांकन तथा प्राप्त फीडबैक के बाद की गई है।' जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अग्निपथ योजना 14 जून 2022 में शुरू की गयी थी और उसके मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि अग्निवीरों का कार्यकाल चार वर्ष का रहेगा और चार वर्ष के बाद इनमें से केवल 25 प्रतिशत को मेरिट के आधार पर स्थायी सैनिक के तौर पर सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेनाओं की सिफारिश पर सरकार ने अग्निवीरों के अब तक के सभी बैचों के अग्निवीरों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। चार वर्ष पूरे होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर स्थायी किया जायेगा जबकि बाकी बचे 75 प्रतिशत को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो वर्ष के बाद 75 प्रतिशत में शामिल सभी अग्निवीरों को सेनाओं में स्थायी सैनिक बनने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी अग्निवीरों को उनकी इच्छा तथा सेनाओं के चयन मानदंडों के आधार पर सेनाओं में स्थायी सैनिक बनाया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि दो वर्षों के सेवा विस्तार के दौरान अग्निवीरों को पहले वर्ष 43 हजार 500 और दूसरे वर्ष 47 हजार 500 रूपये का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 10 लाख 92 हजार रूपए की सेवा निधि भी दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर नियमित किए गए 25 प्रतिशत अग्निवीर सैनिक बनने के बाद वरिष्ठता में बाद में नियमित किए जाने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों से वरिष्ठ रहेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद देश के विभिन्न जिलों में अग्निवीरों की भर्ती का दायरा बढ़ा है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया अधिक मानकीकृत और पारदर्शी रही है। इसके अलावा अग्निवीरों की शारीरिक फिटनेस, मनोबल, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धात्मक भावना और अनुशासन उच्च स्तर का है। सेवा के दौरान अग्निवीरों को कौशल, तकनीकी क्षमता और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढने के अवसर दिए गए है। महिलाओं को रक्षा बलों की विभिन्न शाखाओं में शामिल किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अग्निवीर छह वर्ष के बाद सेनाओं में नियमित सैनिक बनने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो उसे बाहर आने पर अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती में आरक्षण या वरीयता दिए जाने के बारे में लिए गए सरकार के निर्णयों का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि ये निर्णय केवल उन अग्निवीरों के लिए थे जो चार वर्ष के बाद सेनाओं से बाहर आने वाले थे। श्री वैष्णव ने कहा कि सेनाओं और सरकार दोनों का यह मत है कि अग्निपथ योजना बेहद फायदेमंद रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में इससे पहले भी सुधार और उनकी समीक्षा की जाती रही है और सुधार तथा समीक्षा की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

दुष्कर्म व पॉक्सो मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना 5 साल बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इससे जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये होगा। केंद्र का खर्च निर्भया फंड से वहन किया जाएगा। योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इनमें विशेष रूप से पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित अदालतें भी शामिल होंगी। वर्तमान में 779 एफटीएससी संचालित हैं। इन्हें बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। नई अदालतों की स्थापना उन जिलों में की जाएगी, जहां दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों की लंबित संख्या अधिक है। प्रत्येक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। इससे अदालतों के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाने और पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के निर्धारित वित्तीय ढांचे के अनुसार संचालन खर्च के लिए सहायता दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है। इसके जारी रहने से लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत संवेदनशील गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए विशेष केंद्रों और बच्चों के अनुकूल अदालतों की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि देशद्रोही हैं मोदीः राहुल गांधी

संगरूर,(पंजाब)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नियंत्रण होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि श्री मोदी 'देशद्रोही' हैं और वह आमने-सामने की बहस में पांच मिनट के भीतर इसे साबित भी कर देंगे। श्री गांधी ने यहां बुधवार को 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने बहस करने की चुनौती दी थी।

उन्होंने कहा कि बहस में निर्णायक के तौर पर प्रधानमंत्री जिसे चाहें, उसे बैठा सकते हैं। वह मोहन भागवत या अडानी को भी निर्णायक बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में चर्चा की बात करते हैं लेकिन वहां विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है और उसे बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री उनके सामने बैठकर बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को नियंत्रित करते हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने धमकाकर उनसे पांच मिनट के भीतर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिये। इस समझौते के लिए न तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी गयी और न ही नौकरशाहों से सलाह ली गयी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते से देश के किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोला। ट्रंप लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोल पाते। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री श्री ट्रंप के इस दावे का जवाब क्यों नहीं देते। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसानों, छोटे और मझोले उद्योगों तथा आम कारोबारियों के हितों की रक्षा करने के बजाय बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं।

मोदी आज एशियाई पैरा खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से करेंगे संवाद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर में एशियाई पैरा खेल 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से संवाद करेंगे। इस दौरान वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम में एशियाई पैरा खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। भारत ने इस वर्ष जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में भारत के 97 पैरा खिलाड़ियों ने कुल 114 पदक जीते।

चुनाव आयोग के फॉर्म-6 से संबंधित चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह 19 नवंबर को उन चिंताओं पर सुनवाई करेगा, जो निर्वाचन आयोग के उस स्पष्टीकरण को लेकर जताई गई हैं, जिसमें दिल्ली की मतदाता सूची के ड्राफ्ट से नाम छूट जाने वाले मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 'फॉर्म 6' भरकर फिर से पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि मतदाताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मामला पहले से ही न्यायिक विचार के अधीन है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी से कहा कि वे एक उचित आवेदन दायर करें, जिसमें निर्वाचन आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर लाया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय को बताया



कि मतदाता इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि फॉर्म 6 भरने पर उन पर गलत जानकारी देने का मुकदमा चल सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो लोगों को इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं है। न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो वह निर्वाचन आयोग को दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर से आगे बढ़ाने के लिए कह सकता है। उच्चतम न्यायालय में अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की याचिका में दिल्ली के एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47.56 लाख मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी के तहत हटाए जाने को चुनौती दी है। निर्वाचन आयोग इन हटाए गए मतदाताओं को फिर से नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म 6' भरने को कह रहा है। प्रशांत भूषण की दलील है कि फॉर्म 6 विशेष रूप से 'पहली बार' वोटर बनने वालों के लिए होता है, जिसमें यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक का नाम पहले कहीं नहीं है। पहले से पंजीकृत मतदाताओं से यह फॉर्म भरवाना उन्हें कानूनन मुसीबत में डाल सकता है। इससे पहले 28 अक्टूबर की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं को नए सिरे से आवेदन करने के लिए मजबूर करना गलत है। न्यायालय ने सुझाव दिया था कि जो लोग अपना आवास बदल चुके हैं, उन्हें पते में सुधार के लिए 'फॉर्म 8' भरने की अनुमति दी जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी अहंकार और हताशा का परिणामः भाजपा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर की गयी टिप्पणियों को उनके अहंकार और हताशा का परिणाम बताया है और प्रधानमंत्री को चर्चा की चुनौती देने को संविधान की मूल भावना का अपमान बताया है।



भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से बात करते हुए पंजाब के संगरूर में रैली के दौरान श्री गांधी द्वारा श्री मोदी और श्री शाह को लेकर की गयी टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि श्री गांधी विपक्ष के नेता हैं। यह कांग्रेस के लिए और भी बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने अपने अहंकार और हताशा से प्रेरित होकर पंजाब में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बेबुनियाद टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि पंजाब से नशे को खत्म करने की तय समयसीमा तक केंद्र सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, 'श्री गांधी, शायद आप यह नहीं समझते कि संकल्प का क्या अर्थ होता है और किसी संकल्प को वास्तविकता में कैसे बदला जाता है। यदि आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे नेताओं से सीखिए। गृह मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। केवल नक्सलवाद खत्म कर दिया गया है, बल्कि पिछले 12 महीने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। गत 47 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ हुआ है, जब एक साल की अवधि के दौरान नक्सलवाद के कारण सीआरपीएफ का कोई जवान शहीद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 'हम दोहराना चाहते हैं कि पंजाब दौरे के दौरान श्री गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह भारत के लोगों का अपमान है। यह अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केवल एक सस्ती चाल है।

2027 में फिर भाजपा-एनडीए की सरकार बनना तयः नवीन

गोरखपुर,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर भाजपा-एनडीए की सरकार बनेगी।

गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया है, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति परिवार तक सीमित है। यह अंतर केवल भीड़ का नहीं, बल्कि जनविश्वास का है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देशभर में लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ पार्टी और एनडीए की 100



से अधिक पदयात्राएं हो चुकी हैं। इन यात्राओं में मिल रहे जनसमर्थन से स्पष्ट है कि जनता भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव में हार के बाद कभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तो कभी चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराता है। उन्होंने सवाल किया कि वर्ष 2025 से पहले जब एसआईआर नहीं हुआ था, तब चुनावों में मिली हार के लिए विपक्ष किसे जिम्मेदार ठहराता था। श्री नवीन ने मतदाता सूची में नाम कटने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि मृत, स्थानांतरित और लापता मतदाताओं के नाम पर वह आखिर किसके वोट की मांग कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में संविधान में बदलाव किए गए और डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान हुआ, वही आज संविधान की दुहाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास, रोजगार और सुशासन को बढ़ावा मिला है। भाजपा सरकार ने साढ़े 12 लाख से अधिक युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी है। गोरखपुर में खाद कारखाने सहित विभिन्न संस्थानों के शुरू होने और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। सपा के चुनाव चिह्न साइकिल पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साइकिल पंक्चर हो चुकी है और पंक्चर साइकिल एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं ने कोरोना काल में जनता के बीच रहकर सेवा करने के बजाय घरों में रहना पसंद किया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद की।

पूर्वी दिल्ली में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, 20 हजार से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बुधवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में करकड़ी मोड़ से निर्माण विहार तक निकाली गई इस पदयात्रा में 20 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने, चुनाव आयोग के खिलाफ बिना प्रमाण आरोप लगाने और राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। विकास मार्ग पर आयोजित पदयात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों की राजनीति के विरोध में नारे लगाए तथा लोगों के बीच पर्चे वितरित कर पार्टी का पक्ष रखा। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा के लिए जनजागरण आवश्यक है।



केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति है, तो उन्हें लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक प्रदर्शन और दबाव की राजनीति के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं को विवादों में घसीटने का प्रयास कर रहा है। मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए बड़ी संख्या में सांसदों को ले जाने और इसके बाद राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने के बावजूद विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन पर अनुचित दबाव बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पटना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके स्वर्गीय पिता के विरुद्ध की गई कथित अभद्र टिप्पणी की भी आलोचना की। मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार और दिवंगत परिजनों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय राजनीतिक संस्कृति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का विश्वास ऐसी टिप्पणियों से कमजोर नहीं होने वाला है। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और अराजकता फैलाने वाली राजनीति के विरोध में जनता के बीच जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी को संसद में बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विपक्ष के हर सवाल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अराजकता के पर्याय बन चुके हैं। जनता को गुमराह करने के बजाय कांग्रेस को अपने राजनीतिक अस्तित्व पर आत्ममंथन करना चाहिए। मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, 1984 के सिख नरसंहार और एफआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है और इसी कारण निर्वाचन आयोग की कार्रवाई का विरोध कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। क्या इन राज्यों में पार्टी की लगातार राजनीतिक पराजय का कारण भी वोट चोरी है? मल्होत्रा ने कहा कि ईवीएम की व्यवस्था कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय लागू हुई थी। जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम सही होती है, लेकिन हारने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने और जनता को गुमराह करने तक सीमित रह गई है।

आआपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सीपीसीबी और सीएक्यूएम में दर्ज कराई शिकायत

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों में कथित हेरफेर को लेकर बुधवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आआपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि राजधानी में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है।

भारद्वाज ने शिकायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक्यूआई के आंकड़ों को कृत्रिम रूप से कम दिखाने के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने शिकायत में 3 नवंबर को जहांगीरपुरी स्थित आईटीआई के पास लगे कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) का वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया। भारद्वाज ने बताया कि वीडियो में निगरानी स्टेशन पर सीधे पानी का छिड़काव होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह बुराड़ी के विधायक संजीव झा द्वारा भी 3 नवंबर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक अन्य वीडियो साझा किया गया। आआपा ने आरोप लगाया कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंसर के आसपास पानी का छिड़काव करने से पीएम 2.5 और पीएम 10 के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं और वास्तविक प्रदूषण स्तर से कम एक्यूआई दर्ज हो सकता है। भारद्वाज ने शिकायत में कहा कि जहांगीरपुरी की घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई मॉनिटरिंग व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों का हिस्सा हो सकती है। आआपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यदि एक्यूआई के आंकड़ों को वास्तविकता से कम दिखाया जाता है तो इसका असर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू होने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भी पड़ सकता है। इससे भारी वाहनों पर प्रतिबंध, औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण और धूल प्रदूषण रोकने जैसे जरूरी कदम प्रभावित हो सकते हैं। आआपा ने सीपीसीबी और सीएक्यूएम से दिल्ली के सभी सीएएक्यूएमएस केंद्रों पर कथित भौतिक छेड़छाड़ की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, डीपीसीसी के डेटा अधिग्रहण सिस्टम एवं निगरानी केंद्रों का स्वतंत्र ऑडिट कराने, गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की।

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट की वितरित

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुधवार को दिल्ली सरकार के पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट वितरित की। यह कार्यक्रम महिपालपुर गांव के राजकीय कन्या विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आंगनवाड़ी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। इससे पहले सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी आज देवली विधानसभा क्षेत्र में आंगन के मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने यहां कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को पोषण किट वितरित की। बिधूड़ी ने कार्यक्रम में केंद्र एवं दिल्ली सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। इस अवसर पर पूर्व महापौर आरती मेहरा, जिला अध्यक्ष माया बिष्ट, निगम पार्षद अनीता सतपाल सिंघल, वरिष्ठ भाजपा नेता सतपाल सिंघल, भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष आकृष्ट कौशिक, ओबीसी जिला मोर्चा अध्यक्ष बलराज चौधरी, मंडल अध्यक्ष बलविंदर कौर एवं रेखा चौहान तथा जिला भाजपा उपाध्यक्ष गगन प्रधान एवं रोहित कुड़िया, रोहित चौधरी, रूपचंद थाड़ीवाल और प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया जाता है।

महापौर का स्कूल में औचक निरीक्षण, गंदगी पर नाराजगी

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को निगम विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सुल्तानपुरी के बी-2 में स्थित निगम प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में इधर उधर घूमते छात्रों को देखकर इस अनुशासनहीनता पर नाराजगी जाहिर की और विद्यालय के अध्यापकों की उपस्थिति की भी समीक्षा की। महापौर ने विद्यालय की सुविधाओं का निरीक्षण कर विद्यालय की सफाई व्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और क्षेत्रीय उपायुक्त एवं उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल बुलाकर जवाबदेही सुनिश्चित करने के आदेश दिए एवं विद्यालय प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध छात्रों के लिए पीने के पानी को पिया एवं मध्याह्न भोजन भी चखा।



महापौर ने विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की तथा उनकी बाते और सीखने के प्रति उनकी लगन देखकर प्रसन्नता की अनुभूति की। उन्होंने कहा कि निगम विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं और छात्रों की सुविधाओं एवं शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति गंभीर हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के खातों में वर्दी संबंधी राशि डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की थी। महापौर ने कहा कि बच्चों का बेहतर भविष्य, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरीक्षण निरंतर जारी रहेगे।

नौ वर्षीय छात्रा की स्कूल में अचानक मौत, कार्डियक अरेस्ट का दावा



नई दिल्ली,एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 स्थित लवली हेरिटेज स्कूल में कक्षा तीन की नौ वर्षीय छात्रा की अचानक मौत हो गई। खेलकूद के सत्र से लौटने के बाद छात्रा कक्षा में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन समय पर प्राथमिक उपचार और सीपीआर नहीं दे पाया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि छात्रा खेलकूद की कक्षा से लौटकर कमरे में प्रवेश करती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद शिक्षिका तुरंत उसे संभालने की कोशिश करती है और कुर्सी पर बिठाती है। इसके बाद शिक्षिका छात्रा को लेकर चिकित्सा सहायता के लिए बाहर जाती दिखाई देती हैं। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, छात्रा को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे निर्माण विहार स्थित मलिक अस्पताल रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रबंधन का दावा है कि छात्रा को कार्डियक अरेस्ट आया था। वहीं, परिजनों ने स्कूल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने और छात्रा को तत्काल सीपीआर नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी।

दिल्ली विवि में दो दिवसीय 'रचयिता साहित्य उत्सव' का समापन

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में 'रचयिता फाउंडेशन' की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'रचयिता साहित्य उत्सव' का सफलतापूर्वक समापन हुआ। उत्सव में लोक, साहित्य, भाषा, स्त्री-विमर्श, गांधीवादी विचार, राष्ट्रीय अस्मिता, कविता, रील्स के दौर में पुस्तकों की बदलती भूमिका और पत्रकारिता जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, साहित्यकारों और पत्रकारिता विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में भाग लिया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा, अनूप लाठर, प्रो. रंजन त्रिपाठी एवं रोजगार विथ अंकित के प्रतिनिधि अमर चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया।



उत्सव के पहले सत्र 'साहित्य का लोक और लोक का साहित्य' में प्रो. मंजू मुकुल कांबले ने कविताओं के माध्यम से लोक, भाषा और साहित्य के संबंधों को रेखांकित किया और कहा कि साहित्य लोकजीवन के अनुभवों और संवेदनाओं से जन्म लेकर समाज को समृद्ध करता है। प्रो. अनूप लाठर ने हिंदी और उर्दू सहित भाषाओं के उद्गम पर चर्चा करते हुए कहा कि भाषाओं की जड़ों में लोकभाषाओं की अहम भूमिका रही है और लोकभाषाएं अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर वैश्विक पहचान बना रही हैं। सत्र का संचालन उत्तम कुमार ने किया। 'कविता की भाषा' सत्र में प्रो. रामेश्वर ने कहा कि कविता की भाषा को व्याकरण, शब्दावली, पारंपरिक शिल्प या आलोचना के तय मानकों में सीमित नहीं किया जा सकता। नई पीढ़ी की बोलचाल, स्लैंग और नए भाषिक प्रयोगों को भी उनके अनुभव के संदर्भ में समझना चाहिए। उन्होंने छायावादी कवियों के लेखन में समय के साथ आए बदलावों का भी उल्लेख किया। सत्र का संचालन डॉ. अंजुम शर्मा ने किया। स्त्री विमर्श पर केंद्रित सत्र 'स्त्री का राष्ट्र' में प्रो. भारती गोरे ने कहा कि नारीवाद महिलाओं को कमजोर नहीं, बल्कि सशक्त बनाता है। प्रो. वंदना झा ने अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाओं का उदाहरण देते हुए स्त्री की नेतृत्व क्षमता और समाज को दिशा देने की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रो. बिजयलक्ष्मी नंदा ने कहा कि महिला आंदोलनों की भाषा से अधिक उनके उद्देश्य और लक्ष्य को समझना जरूरी है और समाज से दूसरों पर सवाल उठाने के साथ आत्मचिंतन का भी आह्वान किया। एक अन्य सत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन पर चर्चा हुई, जिसमें वक्ता डॉ. महेश चंद्र शर्मा और संचालक अनिल राजगढ़ रहे। शर्मा ने कहा कि इसे केवल अनेक विचारधाराओं में से एक मानना उचित नहीं, बल्कि यह भारतीय जीवन-पद्धति में सहज रूप से दिखाई देने वाली दृष्टि है, जिसे सामान्य व्यक्ति के दैनिक अनुभवों के माध्यम से समझा जाना चाहिए।

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' की रिलीज पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बुधवार को अभिनेता सनी देओल की आने वाली हिंदी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टरों के समुदाय ने पहले ही एक अन्य रिट याचिका के जरिए यह मुद्दा उठाया है, जो अभी सिंगल बेंच के समक्ष लंबित है। यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही ये याचिकाकर्ता भी डॉक्टर हैं, फिर भी हमें कार्यवाही को कई हिस्सों में बांटने का कोई कारण नहीं दिखता। डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता सिंगल जज के सामने चल रही कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, उन्हें अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने की छूट भी दी गई। ये याचिका डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान ने दायर की थी। इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में डॉक्टरों के खिलाफ शारीरिक हिंसा को वीरतापूर्ण तरीके से दिखाया गया है, और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को अनुचित रूप से सामान्यीकृत किया गया है। सिंगल बेंच ने 2 नवंबर को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे इस याचिका पर जवाब मांगा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भ्रष्ट दिखाया गया है और इससे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिलता है। डिवीजन बेंच के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म सार्वजनिक कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिशानिर्देश देने की मांग की थी कि वे फिल्म की जांच करें और इसमें मौजूद कथित आपत्तिजनक दृश्यों या संवादों को हटा दें या उनमें बदलाव करें।

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मिली सहमति

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (क्रिमिनल) अमोल सिन्हा ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल हेड रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। वकील कौशिक चटर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय में रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर सकेंगे। न्यायालय ही इस पर अंतिम फैसला करेगा। उल्लेखनीय है कि साकेत कोर्ट में सीजेएम अभिनव पांडे की कोर्ट में रत्ना सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी। रत्ना सिंह ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और सीईओ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जाने से रोका। उन्होंने पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। न्यायालय ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। आदेश के बाद रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जज पर किसी 'आका' / 'मालिक' के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। वकील कौशिक चटर्जी ने 14 और 28 अक्टूबर को शिकायत देकर कहा कि ये पोस्ट न्यायिक अधिकारी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और कोर्ट की गरिमा को कम करती है। 2 नवंबर को एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये पोस्ट न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(2) के दायरे में आती है। इसलिए क्रिमिनल कंटेंप्ट की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है।

पत्रकार की पत्नी के इलाज का खर्च देने से सरकार नहीं कर सकती इनकार

नई दिल्ली,एजेंसी। पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता एक गंभीर विषय बनी हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 नंवबर के फैसले में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किए जाने के कारण यदि सामान्य मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उन्हें मजबूरी में निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है, तो सरकार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने रविंदर गुप्ता बनाम स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में यह फैसला 2 नंवबर को सुनाया है।

याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता, दिल्ली सरकार से मान्यता-प्राप्त पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के उपचार पर सर गंगा राम अस्पताल और सर गंगा राम सिटी अस्पताल में खर्च हुई 11,83,105.21 रुपये की शेष राशि की प्रतिपूर्ति की मांग की थी। उनकी पत्नी दाहिनी फीमोरल धमनी के संक्रमित छद्म-धमनीविस्फार से पीड़ित थीं और उन्हें तत्काल संवहनी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 4 अगस्त 2021 को उनकी पत्नी को जीबी पंत अस्पताल में जांच के बाद सर गंगा राम अस्पताल रेफर किया गया था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में आवश्यक संवहनी शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उस समय कोविड-19 महामारी के कारण कई सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, जिससे सामान्य मरीजों के उपचार की उपलब्धता प्रभावित हुई थी।

याचिकाकर्ता गुप्ता ने दिल्ली प्रेस रिपोर्टर एवं चिकित्सा सहायता नियम, 1955 के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया था। 15 नवंबर 2011 की अधिसूचना के नियम 7 में आपातकालीन परिस्थितियों में मान्यता-प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार कराने की अनुमति का प्रावधान है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने 21 जुलाई 2025 के पत्र के माध्यम से यह कहते हुए प्रतिपूर्ति से इनकार कर दिया था कि मरीज की शल्य चिकित्सा आपातकालीन प्रकृति की नहीं थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मामले के तथ्यों और अस्पताल द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाणपत्र का परीक्षण करते हुए पाया कि मरीज को तत्काल भर्ती और उपचार की सलाह दी गई थी। जीबी पंत अस्पताल का रेफल तथा सर गंगा राम अस्पताल का आपातकालीन प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपचार की आवश्यकता आपात परिस्थितियों में उत्पन्न हुई थी। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि प्रतिवादी पक्ष अस्पताल के आपातकालीन प्रमाणपत्र का खंडन करने में विफल रहा। सरकार की ओर से दलील दी गई कि नियम 7 के प्रावधान के तहत प्रतिपूर्ति का लाभ तभी दिया जा सकता है, जब सरकारी अस्पतालों में हड़ताल हो। केवल अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किए जाने को हड़ताल के समान नहीं माना जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने कहा कि मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण से सरकारी अस्पताल में हड़ताल और उसे कोविड अस्पताल घोषित किए जाने की परिस्थितियों में कार्यात्मक समानता है। दोनों ही स्थितियों में सामान्य मरीजों को नियमित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं और उन्हें उपचार के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों परिस्थितियों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मरीज के लिए उनका परिणाम समान हो सकता है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा 21 जुलाई 2025 को जारी प्रतिपूर्ति अस्वीकार करने वाले पत्र को निरस्त कर दिया। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सर गंगा राम अस्पताल और सर गंगा राम सिटी अस्पताल में पत्नी के उपचार पर हुए 11,83,105.21 रुपये के शेष चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति आठ सप्ताह के भीतर की जाए। न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी दी कि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी से सरकार उक्त राशि की वसूली कर सकती है। इस फैसले के आने के बाद मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति के महासचिव रजनीकांत तिवारी ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोर्ट के इस निर्णय का महत्व केवल एक पत्रकार को चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति मिलने तक सीमित नहीं है। यह पत्रकारों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों, उनके परिवारों की चिकित्सा सुरक्षा और सरकारी चिकित्सा सहायता नियमों की व्यावहारिक व्याख्या के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सरकारी, निजी और अर्द्धसरकारी अस्पतालों में उपचार तथा चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से संबंधित नियमों को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की आवश्यकता सामने आती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला सरकारों और संबंधित विभागों के लिए इस दिशा में चिकित्सा सहायता नियमों की समीक्षा करने तथा पत्रकारों के हित में स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

दिल्ली में यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित आरोपित यूएई से भारत लाया गया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के यौन उत्पीड़न के एक मामले में वांछित आरोपित सजीर पल्ली मूप्पम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत प्रत्यर्पण किया है। इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रहे आरोपित को बुधवार को प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत लाया गया। सीबीआई के अनुसार, इस कार्रवाई में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के साथ समन्वय किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि आरोपित ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर 20 वर्षीय युवती को जबरन नशीला पदार्थ दिया था, जिससे वह बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद आरोपित उसे एक होटल में ले गया और पहचान छिपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर होटल में कमरा लिया। आरोप है कि वहां उसने युवती के साथ उसकी सहमति के बिना यौन उत्पीड़न किया। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई। मामले में सक्षम अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से आरोपित के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था।

एक नजर

बीएसएफ डीआईजी के बेटे की 11वीं मंजिल से गिरने से मौत

गुरुग्राम,एजेंसी। सेक्टर-85 की द लीफ सोसाइटी में बीएसएफ के डीआईजी के 28 वर्षीय बेटे की 11वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही खेडक़ी दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची व जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) के पद पर तैनात सत्यवान वर्तमान में ओडिशा के कोरापुट में तैनात हैं। उनके 28 वर्षीय बेटे असीम सेक्टर-85 की द लीफ सोसाइटी में रहते थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे टावर नंबर-8 के 11वीं मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 10-बी की बालकनी से गिरने के बाद असीम गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज आवाज सुनकर नीचे मौजूद सुरक्षाकर्मी और निवासी मौके पर पहुंचे, जहां युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। अचानक हुई इस घटना से सोसाइटी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने असीम को आरवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। खेडक़ी दौला थाना पुलिस ने घटनास्थल और संबंधित फ्लैट को सील कर दिया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल युवक की मौत के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह हादसा है या आत्महत्या या फिर कोई और वजह है, इस पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। परिवार के सदस्यों और सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही डीआईजी सत्यवान ओडिशा से गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं।

गाजियाबाद में खुला पहला गोबर प्लांट, 150 टन गोबर से तैयार होगा 70 टन बायोफ्यूल

गाजियाबाद। कवि नगर जोन में स्थापित गाजियाबाद नगर निगम के पहले गोबर प्रोसेसिंग प्लांट में लगी तीन मशीनों की मदद से अब प्रतिदिन 150 टन से अधिक गोबर का निस्तारण किया जाएगा। गोबर से रोजाना 70 टन से अधिक बायोफ्यूल बनकर तैयार होगा। इसक इस्तेमाल विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। मंगलवार को महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त द्वारा इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब शहर के अन्य सभी पांचों जोन में भी कुल 25 मशीनें लगाकर इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सड़कों और नालियों में गोबर बहने के कारण शहर में गंदगी और बदबू की गंभीर समस्या बनी रहती थी। स्थानीय निवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों का स्थायी समाधान निकालते हुए नगर निगम ने इस वेस्ट-टू-वेल्थ माडल को धरातल पर उतारा है। यह पूरा प्लांट सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल पर कार्यदायी संस्था के सहयोग से शुरू किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस संयंत्र को स्थापित करने में नगर निगम को अपनी जेब से कोई भी फंड खर्च नहीं करना पड़ा है, जबकि तैयार बायोफ्यूल और खाद से निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। गोबर से बायोफ्यूल बनने के बाद बचे हुए वेस्ट से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी। जिसे शहर की नर्सरियों और पार्कों के पेड़-पौधों में उपयोग में लाया जाएगा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्लांट से शहर में पशुपालकों को राहत मिलेगी। पशुपालकों से अपील की गई है कि वह अपने गोबर को नालियों में बहाने के बजाय सीधे इस प्लांट तक पहुंचाएं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथिलेश व उद्यान प्रभारी डा. अनुज मौजूद रहे।

पुलिस मुठभेड़ में एक गिरफ्तार

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की थाना बड़ौत पुलिस और वांछित बदमाश के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में अपराधी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। झगड़े के दौरान तमंचे से फायरिंग करने वाले अपराधी की धरपकड़ के लिए तीन नवंबर देर रात को थाना बड़ौत पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और वांछितों की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा संख्या 758/26 में वांछित एक अभियुक्त जंगल ग्राम लुहारी में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।

खुद को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे कब्जे में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मैनपाल पुत्र आजाद निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत के रूप में हुई है। यह पूरा मामला 31 अक्टूबर 2026 का है। ग्राम हटाना निवासी तेजू पुत्र हुक्मी ने थाना बड़ौत में तहरीर दी थी कि खेड़ा इस्लामपुर के दिनेश उर्फ छोटू, मैनपाल, बंटी, टिंकू, अमित, आजाद, बली, राजू, राजन, अंकित, मनु, राजीव उर्फ काला, चरना सहित 13 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की। मारपीट में बिहारी, बिल्लू, सोनू समेत कुल 7 लोग घायल हुए थे, जिनमें दो महिलाएं और एक युवती भी शामिल थीं।

गुरुग्रामः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 व तीन तलाक के निर्णयों पर किया संवाद



गुरुग्राम,एजेंसी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गुरुकमल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया तथा उनके साथ आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के संगठन के प्रति समर्पण, लंबे संघर्ष और योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा की संगठनात्मक शक्ति के पीछे उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम और निष्ठा है, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए प्रमुख निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने तथा तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साझा की। उन्होंने सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुचाने का आह्वान किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीयता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके लिए केवल संगठन के सदस्य नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता उनसे कभी भी, किसी भी समय नि:संकोच मिल सकते हैं। चंडीगढ़ स्थित उनके मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए सदैव खुले हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान, आत्मीयता और संगठन के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। जिला मीडिया प्रभारी अजय दुआ ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर तथा पटौदी विधायक बिमला चौधरी मौजूद रही।

साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का बेरोकटोक इस्तेमाल, निगम पर उठा सवाल

साहिबाबाद,एजेंसी। प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल साप्ताहिक बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-15 में हर सोमवार को लगने वाले बाजार में इसको देखा जा सकता है। निवासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इसकी शिकायत की है।

निवासियों का कहना है कि बाजार लगने के दूसरे दिन यानि मंगलवार को सड़कों पर जगह-जगह पॉलीथीन बिखरी रहती है। निगम के वाहन इन्हें भरकर ले भी जाते हैं लेकिन बाजार में इसकी जांच नहीं की जाती। शिखर एन्क्लेव निवासी संदीप गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू किया था। निर्धारित मानकों से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी रोक है।

इसके बावजूद इस साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन के धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है। इस पर संबंधित विभाग की निष्क्रियता से रोक नहीं लग पा रही है। सड़क पर पालीथीन बिखरी होने से सड़कें, फुटपाथ और हरित क्षेत्र प्लास्टिक कचरे से पट जाते हैं। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन न केवल शहर की स्वच्छता पर दाग है, बल्कि नालियों के अवरुद्ध होने, मिट्टी के प्रदूषण और बेसहारा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। वसुंधरा जोन के प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि समय-समय पर पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा माल जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। जल्द ही साप्ताहिक बाजारों में अभियान को शुरू किया जाएगा।

एनसीआर में दिवाली पर जला सकेंगें ग्रीन पटाखे, वह भी तीन घंटे

गुरुग्राम,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर क्षेत्र के गुरुग्राम जिला में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नीरी (एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लाइसेंस चार नवंबर से छह नवंबर 2026 तक अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार नागरिक सात व आठ नवंबर 2026 को सुबह छह बजे से सात बजे तक तथा रात आठ बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू हो जाएगा। इसकी निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें भी गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यही प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानी से बचाना है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लिए जाएंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

पंजाब नेशनल बैंक के खाते से करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप में बैंक कर्मचारी और सहायक गिरफ्तार

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



नोएडा। ग्रेटर नोएडा के एच्क्षर गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के खातों से 10.24 करोड़ रुपये गायब करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बैंक शाखा की एक महिला ऑफिस असिस्टेंट दीपांशी और उसका निजी सहयोगी आशुतोष कुमार पाठक शामिल है। आरोप है कि दोनों ने मिलीभगत कर ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति के रकम निकाली और उसे हड़प लिया। सीबीआई ने आशुतोष को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। वहीं दीपांशी की गिरफ्तारी की लोकेशन सीबीआई ने अभी साफ नहीं की है।

सीबीआई के मुताबिक, मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद आशुतोष पाठक को पुणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली गई है। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रकम के लेनदेन, अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोप है कि दीपांशी ने आशुतोष और अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत और साजिश कर करोड़ों रुपये खातों से निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर किए। बैंक खातों से बिना अधिकृत अनुमति के डेबिट ट्रांजैक्शन किए गए। इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 29 अक्टूबर 2026 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब जांच के दौरान दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने आज जारी अपनी एक प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है। दर्ज केस में महिला कार्यालय सहायक के साथ एक निजी व्यक्ति और अन्य अज्ञात लोगों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। ऐसे में जांच एजेंसी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि खातों से निकाली गई रकम किन खातों में भेजी गई और इस पूरी प्रक्रिया में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। साथ ही बैंक के आंतरिक लेनदेन, अनधिकृत डेबिट और रकम के ट्रांसफर से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जाएगी।

फरीदाबाद में साइबर ठगी के दो आरोपित गिरफ्तार



फरीदाबाद,एजेंसी। साइबर थाना एनआईटी की टीम ने साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में टेलीग्राम के माध्यम से निवेश पर मुनाफे का लालच देकर 3,67,824 रुपये की ठगी की गई, जबकि दूसरे मामले में गैस एजेंसी की फर्जी केवाईसी एप्लीकेशन भेजकर मोबाइल हैक कर खाते से 20 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता अनुसार गांव अनंगपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 सितंबर को उसके टेलीग्राम पर निवेश कर मुनाफा कमाने का संदेश आया था।

शुरुआत में उसने 374 रुपये निवेश किए, जिसके बदले उसे 600 रुपये वापस मिले। इससे उसका विश्वास बढ़ गया और ठगों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर उससे अलग-अलग किस्तों में कुल तीन लाख 67 हजार 824 रुपये जमा करवा लिए। बाद में आरोपितों ने रकम फ्रीज होने का बहाना बनाकर दो लाख 69 हजार 880 रुपये और जमा करवाने की मांग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता को अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला। मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर थाना एनआईटी की टीम ने बिक्रम निवासी सेक्टर-25, मदनपुरी, पंचकूला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने एक जानकार के माध्यम से अपना बैंक खाता आगे ठगी करने वालों को उपलब्ध करवाया था। आरोपी के खाते में ठगी के 68 हजार रुपये प्राप्त हुए थे। दूसरे मामले में उत्तम नगर, फरीदाबाद निवासी शिकायतकर्ता का इंडेन गैस कनेक्शन से सिलेंडर बुक नहीं हो रहा था। इस पर उसने गूगल पर रिच फ्लेम गैस एजेंसी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। वहां मिले नंबर पर कॉल नहीं लगने के कुछ समय बाद उसके पास दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताते हुए केवाईसी लंबित होने की बात कही और ऑनलाइन केवाईसी के लिए इंडेन गैस के लोगो वाली एक एप्लीकेशन भेजी। एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन हैक हो गया और उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। बाद में बैंक स्टेटमेंट चेक करने पर पता चला कि साइबर ठगों ने उसके खाते से 20 हजार रुपये निकाल लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विसंत कुमार निवासी गांव बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने पिता का बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया हुआ था। उक्त खाते पर अन्य राज्यों में साइबर ठगी के सात मामले दर्ज पाए गए हैं। आरोपी द्वारा उपलब्ध करवाए गए खाते में ठगी के 10 हजार रुपये प्राप्त हुए थे।

जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन

गुरुग्राम। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने कारागार का निरीक्षण किया।

सचिव निशा ने बताया कि जेल लोक अदालत का उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिल सके। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने बंदियों को विधिक सहायता, नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया।

नूंहः विद्यार्थियों ने सीखी पानी की शुद्धता जांचने की तकनीक

नूंह। विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर नमक के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पानी की गुणवत्ता और शुद्धता जांचने की विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों को समझा तथा प्रयोगशाला में पानी के परीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंडल नंबर-1 कार्यालय परिसर स्थित जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला में तैनात सहायक इरफान ने विद्यार्थियों को पानी की गुणवत्ता जांचने के विभिन्न तरीकों से अवगत करवाया। उन्होंने पीएच, टीडीएस, कठोरता, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट सहित पानी में मौजूद विभिन्न रासायनिक तत्वों की जांच प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में निर्धारित मानकों के अनुसार पानी का परीक्षण किया जाता है, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर उपमंडल अभियंता अजय कांगड़ा ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किताबी शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है। इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों में जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल और जल गुणवत्ता के प्रति वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। जिला सलाहकार नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि जल जीवन का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल के महत्व तथा उसकी गुणवत्ता के निर्धारित मानकों की जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में पानी की जांच की प्रक्रिया से रूबरू करवाने का उद्देश्य उन्हें जल संरक्षण और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता शकील अहमद, मोहम्मद अबरार, बीआरसी मोहम्मद जैकम तथा लैब सहयोगी वाहिद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

गुरुग्रामः नागरिक से दुर्व्यवहार पर पटवारी सस्पेंड, प्रॉपर्टी आईडी में गलती पर एक्शन

गुरुग्राम। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आमजन की शिकायतों और लापरवाही अधिकारियों पर कार्रवाई की। सीएम ने गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले अधिकारी का 50 प्रतिशत वेतन काटने के आदेश दिए। साथ ही एक नागरिक से दुर्व्यवहार करने पर नगर निगम के पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए।

इस बैठक में कुल 15 परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष चार मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर परिषद पटौदी-जाटौली मंडी क्षेत्र से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी के मामले को गंभीरता से लिया। जांच में सामने आया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारियों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सेलरी काटने, उनके चार्जशीट करने तथा हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में एक नागरिक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के पटवारी द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया।

दो दिन से लापता युवक की गला रेतकर हत्या

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद में बुधवार सुबह एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना सरूरपुर गांव की है। उसका शव खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मृतक की पहचान गांव के ही सचिन (22) के रूप में हुई है। वह दो दिन से लापता था। परिवार का कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सचिन के पिता जगबीर ने बताया कि वे सरूरपुर के श्याम नगर में रहते हैं। सुबह एक युवक उनके पास आया और सूचना दी कि सचिन का शव खेत में पड़ा है। वह मौके पर पहुंचे तो सचिन के गले पर चोट के निशान थे। सचिन सोमवार से लापता था। वह एक कंपनी में काम करता था और अविवाहित था। पिता ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। सचिन की बड़ी बहन ने बताया कि वह किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करता था। हालांकि, उसे शराब पीने की आदत थी। उन्हें नहीं पता कि सचिन की हत्या किसने की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों ने उनका इकलौता भाई छीन लिया। मौके पर पहुंचे एक पड़ोसी ने बताया कि सचिन किसी से लड़ाई नहीं करता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि किसने उसकी हत्या की। अगर शराब पीकर उसका किसी से झगड़ा भी हुआ होगा तो इतनी बेरहमी से गला नहीं काटना चाहिए था।



मुजेसर थाना प्रभारी पुरन सिंह ने कहा- सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगी हुई हैं। आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अभी कारणों का पता नहीं लग पाया है।

ट्रंप के लाल तेवरों के खिलाफ नीली सुनामी

पुष्परंजन



'ब्लू सुनामी' कहिए इसे। यह आधुनिक इतिहास में किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ सबसे बड़े जनादेशों में से एक रहा है। मतदाताओं के पास ट्रम्प की निरंकुश सत्ता को नकारने, ईरान में उनके अलोकप्रिय युद्ध, जीवन-यापन की भारी-भरकम लागत को कम करने में उनकी विफलता और पूरी दुनिया में आर्थिक अफरा-तफरी मचाने के खिलाफ अपना फैसला सुनाने का मौका था। अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रम्प समर्थकों के 'एमएजीए' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) के एकाधिकार को जबरदस्त 'ब्लू वेव' के जरिये समाप्त कर दिया। निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और ऊपरी सदन 'सीनेट' पर अब डेमोक्रेट्स का नियंत्रण दिखने लगा है। इससे डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ़रीज़ के लिए इस सदन का पहला अश्वेत स्पीकर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यकीनन इस कालखंड के सबसे बड़े इस्राइल समर्थक राष्ट्रपति रहे हैं। इसलिए उनकी यह घोषणा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्राइल को 4 बिलियन डॉलर की वार्षिक सहायता देना बंद कर देगा, आश्चर्यजनक थी। इस घोषणा को भूकंपीय थरथरी से कम मत मानिए, जिसे तेल अवीव तक तीव्रता से महसूस किया गया। नेतन्याहू के कट्टर समर्थकों का विचार भी बदलने लगा। वे मानने लगे कि ट्रम्प से मिलकर उन्होंने देश को धोखा दिया है। पिछले सप्ताह के चुनाव में कोई स्पष्ट विजेता नहीं होने और नेतन्याहू के भविष्य पर अनिश्चितता के बाद इस्राइल राजनीतिक अधर में है। 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता बंद कर देने की घोषणा ने दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे ठीक एक सप्ताह पहले इस्राइल में चुनाव हुए थे, जिसमें नेतन्याहू ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनके संबंधों से रणनीतिक अवसर मिलते हैं। ट्रम्प के ताजा बयानों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच इस सहायता को समाप्त करने को लेकर महीनों पहले ही सहमति बन गई थी, जबकि मौजूदा समझौता 2028 तक लागू रहना था।

ट्रम्प ने दावा किया कि खुद नेतन्याहू ने ही इस बदलाव का प्रस्ताव दिया था। आखिर क्यों? क्या नेतन्याहू ने मान लिया कि वे सरकार नहीं बना पाएंगे? बना भी ली, तो मनमर्जी चला नहीं पाएंगे। और जब इस्राइल का नियंत्रण किन्हीं और हाथों में चला जाए, तो ट्रम्प से कहकर उसकी डोर क्यों न काट ली जाए। हालांकि, नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से यह वकालत की थी कि अगले एक दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसका असर गठबंधन बनाने की बातचीत पर भी पड़ने लगा है। जो पार्टियां थोड़ा-बहुत नेतन्याहू के नेतृत्व को बर्दाश्त कर गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने पर विचार कर रही थीं, अब उनके नेता बिदकने लगे हैं। उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि भविष्य के सरकारी बजट पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कैसे संभाला जाएगा? ट्रम्प के कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस्राइल के पास 28 महीने का समय है, जिसमें वह ईरान, गाजा और लेबनान में चल रही प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत कर सकता है। मौजूदा समझौते के तहत इस्राइल को सालाना 3.8 अरब डॉलर मिलते हैं, जिसमें 3.3 अरब डॉलर की सैन्य फंडिंग और 500 मिलियन डॉलर संयुक्त मिसाइल-रक्षा कार्यक्रमों के लिए शामिल हैं। यदि इस सहायता को जल्दबाजी में वापस लिया जाता है, तो रक्षा खरीद, बजट योजना और महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने को लेकर तुरंत सवाल खड़े हो जाएंगे। विदेश नीति के ऐसे विश्लेषक, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों प्रशासनों में काम कर चुके हैं, मानते हैं कि इस्राइल की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे सैन्य उपकरण खरीदने के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं है। वैश्विक मामलों के विश्लेषक और नई किताब 'ब्रिंक' के लेखक ब्रेट मैकगर्क भी उनमें से एक हैं। अमेरिका में राजनीतिक हालात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेट्स ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए हाउस और सीनेट, दोनों पर अपना नियंत्रण बना लिया है। डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारी अलोकप्रियता का फायदा उठाया और इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वे उनके कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में उन पर लगाम रख सकें। डोनाल्ड ट्रम्प का वर्तमान राष्ट्रपति कार्यकाल जनवरी, 2029 में समाप्त होना तय है। लेकिन तब तक क्या वे शांत बैठेंगे? ट्रम्प ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को बताया कि वे नतीजों को स्वीकार करेंगे। इससे फिलहाल उन सवालों पर विराम लग गया है कि क्या वे इन नतीजों को चुनौती देंगे।

ट्रम्प इतनी आसानी से पराजय स्वीकार करने वाले प्राणी नहीं हैं। उन्हें अपने 'वीटो' पर भरोसा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि वे सदन में डेमोक्रेट-समर्थित कानूनों को रोकने के लिए 'वीटो पावर' का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फॉक्स न्यूज के ब्रेट बेयर से कहा, 'यह राष्ट्रपति के पास मौजूद सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है। वे ऐसी चीजें भेजेंगे, जो बिल्कुल बेतुकी होंगी और मैं उन पर वीटो लगा दूंगा। कुछ महीनों तक वीटो लगाने के बाद वे पूछेंगे कि इन कामों को कैसे पूरा किया जाए? और फिर हम मिलकर काम करेंगे।' लेकिन ट्रम्प यह भूल जाते हैं कि अमेरिकी संसद में 'वीटो-प्रूफ बहुमत' भी होता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, धारा 7 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति किसी बिल को वीटो के जरिये अस्वीकार कर देते हैं, तो उसे दोबारा कानून बनाने के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी है। जब किसी एक राजनीतिक दल या गठबंधन के पास दोनों सदनों में यह संख्या बल होता है, तो उसे 'वीटो-प्रूफ बहुमत' कहा जाता है। सितंबर, 2025 में ट्रम्प ने एच-1बी वीजा की फीस 88 लाख रुपये कर दी थी, ताकि यह संदेश जाए कि वे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां सुरक्षित कर रहे हैं। ट्रम्प का 'अमेरिका फर्स्ट', 'टैरिफ बम' और ईरान की तबाही भी अमेरिकी वोटरों को नापसंद आई। सितंबर, 2026 के अंत में हुई फ्लाईदुबई विमान की खौफनाक घटना को भी ट्रम्प और नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने के वास्ते इस्तेमाल किया। ये सारी तदबीरें उलटी पड़ गईं। लगभग दो-तिहाई मतदाताओं का मानना है कि युद्धोन्मादी ट्रम्प ने देश की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है। इससे सबाल्टर्न का जीना मुश्किल हो गया। ज्यादातर मतदाताओं का कहना है कि ट्रम्प देश के हितों के बजाय अपने निजी हितों को ज्यादा अहमियत देते हैं। अमेरिकी वोटरों ने पांच हजार डॉलर का चुग्गा भी नकार दिया। उन्होंने अपने वोट के महत्व को समझा। यह संदेश भारतीय मतदाताओं को भी स्वीकार करना चाहिए।

नौकरी की असुरक्षा, व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के भविष्य की चिंता, बुजुर्गों का अकेलापन और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव उसके मन को लगातार मथता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंक और प्रतियोगिता बच्चों के बचपन पर भारी पड़ रहे हैं। कार्यस्थलों पर लक्ष्य, समय-सीमा और प्रदर्शन का दबाव व्यक्ति को मशीन में बदलने लगा है। परिवारों में संवाद की जगह मोबाइल ने और आत्मीयता की जगह औपचारिकताओं ने ले ली है। इस व्यक्तिगत तनाव के ऊपर वैश्विक परिस्थितियों का बोझ भी कम नहीं है। युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की खबरें मनुष्य के भीतर भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित करती हैं। दुनिया के किसी कोने में होने वाला संघर्ष अब केवल उस क्षेत्र की समस्या नहीं रहता, बल्कि संचार माध्यमों के कारण पूरी मानवता की सामूहिक चिंता बन जाता है। इस प्रकार तनाव की सीमाएं घर की चारदीवारी से निकलकर राष्ट्रों और महाद्वीपों तक फैल गई हैं। तनाव को यदि समय रहते समझा और नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह शरीर और मन दोनों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव से नींद में गड़बड़ी, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां, चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाग्रता में कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

मन की शांति में ही जीवन की सच्ची समृद्धि

ललित गर्ग



जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य ने संसार को सुविधाओं से भर दिया, लेकिन स्वयं के भीतर सुकून के लिए जगह कम कर ली। आज हमारे पास समय बचाने के असंख्य साधन हैं, पर समय का अभाव है, संवाद के अनगिनत माध्यम हैं, पर आत्मीयता का अकाल है, भौतिक समृद्धि के नए प्रतिमान हैं, लेकिन मानसिक शांति निरंतर दूर होती जा रही है। आधुनिक मनुष्य की इस विरोधाभासी स्थिति का सबसे बड़ा नाम है-तनाव। तनाव अब केवल मन की बेचैनी नहीं, बल्कि हमारे समय की एक गंभीर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और वैश्विक चुनौती बन चुका है। इसी चुनौती के प्रति चेतना जगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसकी थीम है- ''तनाव-मुक्ति और कल्याण के भविष्य को आकार देना तथा कार्यस्थल को फिर से मानवीय बनाना।'' यह विषय हमें याद दिलाता है कि कार्यस्थल केवल उत्पादन और उपलब्धियों का केंद्र नहीं, बल्कि मनुष्य की संवेदनाओं, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य का भी स्थान होना चाहिए। आज का मनुष्य सुबह आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद होने तक एक अदृश्य दौड़ में शामिल है। नौकरी की असुरक्षा, व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के भविष्य की चिंता, बुजुर्गों का अकेलापन और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव उसके मन को लगातार मथता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंक और प्रतियोगिता बच्चों के बचपन पर भारी पड़ रहे हैं। कार्यस्थलों पर लक्ष्य, समय-सीमा और प्रदर्शन का दबाव व्यक्ति को मशीन में बदलने लगा है। परिवारों में संवाद की जगह मोबाइल ने और आत्मीयता की जगह औपचारिकताओं ने ले ली है।

इस व्यक्तिगत तनाव के ऊपर वैश्विक परिस्थितियों का बोझ भी कम नहीं है। युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की खबरें मनुष्य के भीतर भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित करती हैं। दुनिया के किसी कोने में होने वाला संघर्ष अब केवल उस क्षेत्र की समस्या नहीं रहता, बल्कि संचार माध्यमों के कारण पूरी मानवता की सामूहिक चिंता बन जाता है। इस प्रकार तनाव की सीमाएं घर की चारदीवारी से निकलकर राष्ट्रों और महाद्वीपों तक फैल गई हैं। तनाव को यदि समय रहते समझा और नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह शरीर और मन दोनों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव से नींद में गड़बड़ी, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां, चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाग्रता में कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तनाव मनुष्य की निर्णय क्षमता को कमजोर करता है और उसके संबंधों में कटुता घोल देता है। कहावत है-'चिंता चिता समान है।' यह केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन का गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं को वर्तमान की खुशियों पर हावी कर देती है। इसलिए तनाव से मुक्ति का पहला कदम है-अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना, समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान की दिशा में विवेकपूर्ण प्रयास करना। इस संदर्भ में जैन धर्म के महान आध्यात्मिक आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा विकसित एवं व्यवस्थित की गई प्रेक्षाध्यान पद्धति तनावमुक्त जीवन का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग प्रस्तुत करती है। प्रेक्षाध्यान का मूल भाव है-देखना, जागरूक होकर देखना और अपने भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाओं को निष्पक्ष भाव से समझना। यह केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार करने की वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक साधना है। आचार्य महाप्रज्ञ ने ध्यान, श्वास-प्रेक्षा, शरीर-प्रेक्षा, चौतन्य-केंद्र प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा जैसे प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य को अपने मन, शरीर और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा दी।

प्रेक्षाध्यान का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है-भावनात्मक संतुलन। क्रोध, भय, ईर्ष्या, आवेश और निराशा जैसी वृत्तियों को पहचानकर उनके परिष्कार का प्रयास करना तनाव प्रबंधन की दिशा में सार्थक कदम है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का नियमित ध्यान, श्वास पर एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के जीवन में धैर्य, सहनशीलता तथा मानसिक स्थिरता विकसित कर सकते हैं। इस साधना का संदेश है कि परिस्थितियों को हमेशा बदलना संभव नहीं, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलना हमारे हाथ में है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा भी तनावमुक्त जीवन का अनमोल दर्शन प्रस्तुत करती है। उपनिषदों का आत्मबोध, गीता का निष्काम कर्मयोग, भगवान महावीर का समता दर्शन, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग और पतंजलि का अष्टांग योग मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने की प्रेरणा देते हैं। गीता का संदेश है-कर्म करो, फल की चिंता में स्वयं को मत उलझाओ। इसका अर्थ कर्म से पलायन नहीं, बल्कि परिणाम के अनावश्यक भय से मुक्त होकर पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। योग, प्राणायाम, ध्यान, मौन, स्वाध्याय और नियमित दिनचर्या मनुष्य को मानसिक संतुलन प्रदान करने के प्रभावी माध्यम हैं। हमारी त्योहार संस्कृति भी तनाव के विरुद्ध एक सुंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक औषधि है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प देती है। होली मन के पुराने विकारों और कटु स्मृतियों को रंगों में बहाकर संबंधों में नई आत्मीयता भरने का अवसर देती है। रक्षाबंधन रिश्तों की सुरक्षा और विश्वास का उत्सव है। ईद भाईचारे, सेवा और साझी खुशियों का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम, करुणा और क्षमा की प्रेरणा देता है। पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि, क्षमाभाव, संयम और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। विशेषकर क्षमापना का भाव मनुष्य के भीतर वर्षों से संचित कटुता और प्रतिशोध की गांठें खोल सकता है। त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी है जब वे केवल बाहरी सजावट और खर्च तक सीमित न रहकर मनुष्यों को मनुष्यों के करीब लाएं। सामूहिक उत्सव, पारिवारिक मिलन, लोकगीत, संगीत, सेवा और प्रकृति के साथ जुड़ाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तनावमुक्त समाज के निर्माण में कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों और परिवारों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कार्यालयों में मानवीय व्यवहार, काम और विश्राम के बीच संतुलन, सहकर्मियों के प्रति संवेदनशीलता तथा मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों की तुलना करने के बजाय उनकी प्रतिभा को समझना आवश्यक है। परिवारों में एक-दूसरे को सुनने, साथ बैठने और भावनाओं को साझा करने की संस्कृति विकसित करनी होगी। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, प्रकृति के सान्निध्य और डिजिटल माध्यमों के विवेकपूर्ण उपयोग को जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। गंभीर या लगातार बने रहने वाले तनाव में मनोवैज्ञानिक अथवा योग्य चिकित्सक की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। वस्तुत: तनाव से मुक्ति का अर्थ चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच भी स्वयं को संभालकर रखना है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, अपेक्षाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन इन सबके बीच मनुष्य अपने भीतर शांति का एक ऐसा दीप जला सकता है, जिसकी रोशनी बाहरी अंधेरों से प्रभावित न हो। हमें समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल अधिक पाना नहीं, बल्कि जो प्राप्त है उसमें संतोष, संबंधों में मधुरता और मन में संतुलन बनाए रखना भी है। अंतत: जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हमने कितनी ऊंचाइयां छुईं, बल्कि इस बात में है कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए अपने भीतर की शांति कितनी बचाकर रखी। तनाव को जीवन का स्वामी नहीं, अपनी जागरूकता से नियंत्रित की जाने वाली स्थिति बनाना ही इस दिवस का वास्तविक संदेश है। आइए, हम ऐसी जीवनशैली और ऐसी सामाजिक संस्कृति का निर्माण करें, जहां प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग, उपलब्धियों से अधिक आत्मीयता और भौतिक प्रगति से अधिक मानवीय संवेदनाओं का सम्मान हो। क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और शांतिपूर्ण विश्व की आधारशिला है।

विचार

नदियों की ड्रेजिंग से पहले वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी

कुलभूषण उपमन्यु

पिछले दिनों पंजाब के लुधियाना की संस्था 'पब्लिक एक्शन कमेटी मत्तेवाड़ा सतलुज' ने कुल्लू-मनाली क्षेत्र में ब्यास नदी के तल को गहरा करके किनारों पर कंक्रीट की दीवारें लगाने के काम को बंद करवाने के लिए राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हिमाचल प्रदेश और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस देकर हिमालय क्षेत्र में नदी एवं बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर जारी बहस को पुनर्जीवित कर दिया है, जिस पर स्पष्टता टिकाऊ पर्वतीय विकास के लिए जरूरी है। 2023 में भी बरसात में ब्यास की बाढ़ ने इस क्षेत्र में भारी तबाही की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग भी तबाह हुआ था, जिसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। तब भी नदी की ड्रेजिंग की बात उठी थी। हिमालय नीति अभियान ने तब भी इस पर प्रश्न उठाया था और उचित तकनीकी और वैज्ञानिक शोध के बाद ही कोई निर्णय करने की बात कही थी। 5 अगस्त 2023 को इस विषय पर मेरा भी एक लेख प्रकाशित हुआ था। लुधियाना की संस्था ने एमसी. मेहता बनाम कमलनाथ केस का भी जिक्र किया है, जिसका फैसला 15 मार्च 2002 को हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ब्यास नदी के प्राकृतिक बहाव से छेड़छाड़ पर अंकुश की बात कही और सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत के आधार पर 'प्रदूषक द्वारा भरपाई' को सही ठहराया। उस नोटिस में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में दायर सुगंधा बनाम सड़क परिवहन मंत्रालय के केस का भी हवाला दिया, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हाइवे निर्माण से संबंधित चिंताओं को जायज ठहराया था, जिनमें सड़क के सर्वे से जुड़े मामलों जैसे कि नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर का आकलन करना शामिल है ताकि यह पता लग सके कि कहीं सड़क बाढ़ स्तर के भीतर तो नहीं आ गई है या सड़क निर्माण कार्य बाढ़ निर्मित समतल भूमि में तो नहीं घुस गया है।

जाहिर है कि ड्रेजिंग कार्य सड़क को सुरक्षित करने और नदी के पास की बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले न्यायालय द्वारा दी गई हिदायतों का पालन किया जाए। इस मामले में यदि पालन किया गया है तो बताया जाना चाहिए वरना यह एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने भी मांग की है कि नदी के प्रवाह को बदलने वाली कोई भी कारवाई पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन के बिना करना खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से नदी में जमा मलबा हमेशा समस्या नहीं होता। हिमालयी नदियां अपने साथ भू-क्षरण और चट्टानों के अपक्षय से टूटने से पैदा मलबा अपने साथ लाती रहती हैं और उसे नीचे तक बहा कर जगह-जगह छोड़ती जाती हैं। यही नदी की पारिस्थितिकी का निर्माण करता है। इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नदी की पारिस्थितिकी को हानि पंहुचा सकती है। हिमालयी नदियों के तल सख्त चट्टानों द्वारा नहीं बने हैं। इसलिए ज्यादा मलबा निकाल लेने से तेज ढलानों के कारण नदी तल के भूमि कटाव के बढ़ने और तल के गहरे होते जाने का खतरा पैदा हो सकता है। तल यदि गहरा हो गया तो किनारे पर लगाई गई आरसीसी दीवारों की नींव भी नंगी हो जाएगी और दीवारें अंदर नदी में गिर कर ज्यादा खतरनाक बाढ़ का कारण बन सकती हैं। ड्रेजिंग एक स्थायी समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालयी नदियों द्वारा हर साल लाया जाने वाला मलबा कुछ ही सालों में खाली किए गए स्थलों को भर देगा और जल निकासी की क्षमता फिर से घट जाएगी, यानि बार बार आपको ड्रेजिंग करते रहना पड़ेगा। यह आर्थिक रूप से भी कितना संभव होगा। नदी पर्यावरण का जल जीव भी बड़ा हिस्सा हैं। ड्रेजिंग से उनके आवास तो खत्म ही हो जाएंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए पहले हर नदी घाटी, उसके जलागम क्षेत्र और चट्टानों के प्रकार आदि का वैज्ञानिक निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि कहां कितनी मात्रा में ड्रेजिंग निरापद रूप से बिना नदी के पर्यावरण को हानि पंहुचाए किया जा सकता है। डॉ. नविन जुयाल जैसे हिमालयी नदियों के बारे में वैज्ञानिक समझ रखने वाले विशेषज्ञों की राय तो ड्रेजिंग के विरुद्ध ही है। अत: इस विषय में पुनर्विचार की जरूरत है। हो सकता है कि नदी के जलागम क्षेत्र में मलबा रोकने के लिए किए जाने वाले भू-संरक्षण उपायों की ज्यादा जरूरत हो और वे ज्यादा कारगर हों, इसलिए हालात की यह मांग है कि इस परियोजना पर पुनर्विचार किया जाए और हिमाचल की इन तीन नदियों, सतलुज, ब्यास, और रावी पर पूरा वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए, जिसमें इन नदियों पर बने बांध और जलाशयों पर ड्रेजिंग से पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन किया जाना चाहिए, ताकि बनाई जा चुकी परिसंपत्तियों को भी नुकसान न पहुंचे।

एक नजर

बिहार में चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला, खगड़िया-शिवहर समेत कई जिलों में बदलाव

पटना,एजेंसी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा के चार पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अपराजीत, समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना अतिरिक्त प्रभार-पुलिस अधीक्षक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना पदस्थापित किया गया है। भानू प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान देने के आदेश दिये गये हैं। शैलेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, शिवहर को स्थानांतरित करते हुए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं मो0 मोहिबुल्लाह अंसारी, नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए पुलिस अधीक्षक, शिवहर पदस्थापित किया गया है। जबकि कुमारी ममता कल्याणी (नव प्रोन्नत भा0पु0से0) समादेष्टा, पुलिस-10, पटना बिहार विशेष सशस्त्र को अतिरिक्त प्रभार-समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी राज किशोर सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, पटना सिटी से स्थानांतरित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया गया है।

वैशाली में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिया जायजा



पटना। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी बुधवार को वैशाली पहुंचे। यहां उन्होंने जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन एवं कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही कार्रवाई को समझा। उन्होंने आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में उत्साह है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और बिहार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम से क्षेत्र में विकास और जनकल्याण के प्रति नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे सभी संबंधित लोगों से पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि आयोजन सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस मौके पर भाजपा के विधायक अवधेश सिंह, संजय सिंह, जदयू के सिद्धार्थ पटेल भी उपस्थित रहे।

एमआरएम कॉलेज ने इंटर्नशिप के लिए ईजी इंटर्न कंपनी से किया एमओयू

दरभंगा। एमआरएम कॉलेज में बुधवार को प्रधानाचार्या प्रो. पुष्पम नारायण की अध्यक्षता में ईजी इंटर्न कंपनी के साथ इंटर्नशिप को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। महाविद्यालय प्रशासन ने इसे छात्राओं के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या प्रो. पुष्पम नारायण ने एमओयू की जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक सीबीसीएस प्रणाली के पांचवें सेमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है। छात्राओं के हित को प्राथमिकता देते हुए महाविद्यालय ने यह पहल की है। उल्लेखनीय है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का इस कंपनी के साथ पिछले वर्ष ही एमओयू हो चुका है। महाविद्यालय की इंटर्नशिप नोडल पदाधिकारी डॉ. वंदना कुमारी ने कहा कि इस पहल से छात्राओं को सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्यक्षेत्र से जोड़ने का अवसर मिलेगा। यह इंटर्नशिप पूरी तरह नि:शुल्क होगी। इससे छात्राएं बिना किसी आर्थिक बाधा के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर, कुशल एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेत्तर कर्मी उपस्थित थे। प्रधानाचार्या प्रो. पुष्पम नारायण ने इस पहल के लिए सभी को बधाई देते हुए छात्राओं से नि:शुल्क इंटर्नशिप का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

विधि सेवा दिवस पर 9 नवंबर को चलेगा घर-घर विधिक जागरूकता अभियान

दरभंगा। विधि सेवा दिवस के अवसर पर आगामी 9 नवंबर को जिले के शहरी, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में घर-घर विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की टीम गठित कर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। स्वयंसेवक निर्धारित पंचायतों, गांवों, टोलों, मोहल्लों एवं वार्डों में घर-घर जाकर लोगों को विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता एवं प्रक्रिया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता तथा आपसी सहमति से विवादों के समाधान की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों के अधिकार, संरक्षण एवं बाल-अनुकूल विधिक सेवाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका समूहों एवं सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाई जा सके।

बिहार में ई-कैबिनेट व्यवस्था से फैसले लेने की प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी : सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर दिया जोर- कागजरहित प्रशासन की दिशा में बढ़ेगा राज्य



पटना,एजेंसी। बिहार में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में इसके कार्यान्वयन और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इससे कैबिनेट की निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। कैबिनेट से संबंधित फाइलों का आदान-प्रदान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किए जाने से उनके निष्पादन में लगने वाला समय कम होगा। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।

सम्राट चौधरी ने ई-कैबिनेट व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था कागजरहित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह व्यवस्था बिहार में सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में राज्य की कैबिनेट कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और पेपरलेस बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ई-कैबिनेट व्यवस्था और उसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

दाहा नदी को बचाने के लिए अधिकारियों ने उठायी झाड़ू, जलकुंभी हटाकर किया श्रमदान

सीवान। सीवान की जीवनरेखा मानी जाने वाली बाणगंगा (दाहा) नदी के संरक्षण के लिए बुधवार को जिला प्रशासन और आम नागरिकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। गंगा उत्सव के अवसर पर आयोजित नदी संरक्षण चेतना जागरण कार्यक्रम में अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने नदी को स्वच्छ एवं संरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस दौरान उपविकास आयुक्त अमिताभ सिंह सहित वरीय अधिकारियों ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और नदी के कुछ हिस्सों से जलकुंभी हटाने के लिए श्रमदान किया। जिला प्रशासन और नमामि गंगे अभियान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत गांधी मैदान से नदी संरक्षण चेतना जागरण रैली के साथ हुई। रैली गांधी मैदान से जेपी चौक और पटेल चौक होते हुए दाहा नदी के पुलवा घाट पहुंची। इसमें जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों, स्थानीय नागरिकों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने नदी संरक्षण से जुड़े आकर्षक पोस्टर के माध्यम से लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का संदेश दिया। एनसीसी कैडेट्स बैंड वादन करते हुए रैली में शामिल हुए। पुलवा घाट पर आयोजित मुख्य समारोह में अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक मिन्हाजुद्दीन और नमामि गंगे की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूजा कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रो. रविंद्र नाथ पाठक ने नदी संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जनभागीदारी को जरूरी बताया। इस अवसर पर दाहा नदी के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रो. रीता कुमारी, डॉ. पूजा तिवारी और डॉ. रीता शर्मा को डीडीसी अमिताभ सिंह ने सम्मानित किया। नदी संरक्षण पर पोस्टर बनाने वाले बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता गणेश दत्त पाठक ने किया। इसके बाद पुलवा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर कचरा हटाया। डीडीसी ने जलकुंभी की सफाई में भी श्रमदान किया। डीडीसी अमिताभ सिंह ने कहा कि नदियां हमारी जीवनरेखा हैं। इनके किनारे ही सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। नदियां जैव विविधता के संरक्षण, भूजल स्तर को सुरक्षित रखने और सिंचाई जैसी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि सीवान की दाहा नदी आज संकट में है, लेकिन सामूहिक प्रयास और जनभागीदारी से इसका संरक्षण संभव है।

जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के झूठे नैरेटिव में आने वाली नहीं : नित्यानंद राय

पटना। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को सहरसा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा अभियान के तहत सहरसा पहुंचे राय ने कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता चाहे जितना भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश कर लें, देश की जनता उनके दोहरे चरित्र, नकारात्मक राजनीति और मंशा को समझ चुकी है। जनता अब उनके झूठे नैरेटिव में आने वाली नहीं है। लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी विकासोन्मुखी नीतियों पर है। रेनबो रिसोर्ट जिला परिषद से शहीद चौक तक आयोजित पदयात्रा में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह का जिक्र करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज गांव-गांव, शहर-शहर और देश के हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है- 'मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं।' यह आवाज प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के अन्य नेता लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके इरादों को समझ रही है।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की पहचान भ्रष्टाचार, कुशासन, नीतिगत पंगुता और आतंकवाद के प्रति कमजोर रवैये से रही है। उस दौर में देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और विकास की आकांक्षाओं के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता को गुमराह करने के लिए झूठ और भ्रम का सहारा ले रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य अवश्य हासिल करेगा। देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए राष्ट्रहित, विकास और सुशासन के मार्ग पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी।

टीएमबीयू में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरुः ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाकर ही साकार होगा विकसित भारत का सपना

भागलपुर,एजेंसी। बिहार में भागलपुर जिले के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के ओल्ड पीजी परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में बुधवार को दो दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय सेमिनार का शानदार आगाज हुआ। विश्वविद्यालय के ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता प्रबंधन विभाग तथा औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन विभाग (आईआरपीएम) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी का मुख्य विषय 'विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकास' है। कार्यक्रम में एग्रो-इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर एवं एमबीए विभाग का अकादमिक सहयोग रहा। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रभारी कुलपति व विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. रंजना दुबे, सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. अर्चना कुमारी साह, पूर्व प्रभारी कुलपति प्रो. क्षेमेंद्र कुमार सिंह, पूर्व कुलपति प्रो. उग्र मोहन झा, एग्रो रिसर्च के पूर्व निदेशक प्रो. बालकृष्ण झा, शिक्षाविद् डॉ. राजीव कांत मिश्रा, शांतिनिकेतन से आए मुख्य वक्ता प्रो. देवाशीष सरकार, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. रामसेवक सिंह, प्रो. सी.पी. सिंह, प्रो. सुदामा यादव, संयोजक द्वय प्रो. राजेश कुमार मिश्रा व प्रो. निर्मला कुमारी तथा आयोजन सचिव डॉ. अश्वजीत राठौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

अतिथियों का स्वागत प्रो. निर्मला कुमारी ने किया, जबकि विषय प्रवेश कराते हुए डॉ. अश्वजीत राठौड़ ने सेमिनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) से आए मुख्य वक्ता प्रो. देवाशीष सरकार ने अपने व्याख्यान में कहा कि देश की आजादी के समय जीडीपी में



कृषि की हिस्सेदारी 50 फीसदी थी, जो आज घटकर लगभग 15 फीसदी रह गई है। इसके विपरीत, ग्रामीण श्रमिक बल की भागीदारी बढ़कर 67 फीसदी तक पहुंच चुकी है। उन्होंने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए चार कालखंडों की रणनीति सुझाई। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण (2026-31): सूचना एवं सांख्यिकी की विश्वसनीय नींव मजबूत करना। द्वितीय चरण (2031-35): कौशल विकास, उत्पादकता और अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना। तृतीय चरण (2036-40): स्थानीय उद्यमियों और मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) को सुदृढ़ करना और अंतिम चरण (2041-47): ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन करना। विशिष्ट अतिथि डॉ. राजीव कांत मिश्रा ने भागलपुर के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों—कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम और तसर सिल्क को बेहतर वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की वकालत की। पूर्व प्रभारी कुलपति प्रो. क्षेमेंद्र कुमार सिंह ने इंसानों को कुशल 'संसाधन' के रूप में बदलने की जरूरत बताई, तो वहीं डॉ. उग्रमोहन झा ने योजना, क्रियान्वयन एजेंसी और हितधारकों के बीच त्रिकोणीय समन्वय पर बल दिया।प्रो. रामसेवक सिंह ने मांग आधारित प्रशिक्षण, प्रो. सी.पी. सिंह ने अन्नदाता, युवा व महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा प्रो. सुदामा यादव ने स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार कर युवा आबादी को कुशल बनाने की बात कही। सत्र की अध्यक्षता प्रो. राजेश कुमार मिश्रा ने की और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रंजन कुमार सिन्हा ने किया। उद्घाटन के बाद आयोजित तकनीकी सत्रों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विशेषज्ञों व शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इनमें मुख्य

प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें, डीडीसी ने किशनपुर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का किया निरीक्षण

सुपौल,एजेंसी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने किशनपुर प्रखंड स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूनिट में संचालित कार्यों का जायजा लिया और कचरा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की।

बताया गया कि सुपौल जिले की सभी अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से गांवों से प्लास्टिक सहित अन्य कचरा एकत्रित किया जा रहा है। एकत्रित प्लास्टिक कचरे को जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में भेजा जाता है, जहां उसका प्रसंस्करण एवं उचित निपटान किया जाता है। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक पदार्थों का प्रचलन और उपयोग तेजी से बढ़ा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बोतलों एवं अन्य प्लास्टिक कचरे का बेहतर उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। इससे एक ओर प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान होगा, वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं एवं संवेदकों के साथ बैठक



कर सड़क निर्माण में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अभियंताओं एवं संवेदकों ने भी इस पहल पर सहमति जताते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आगे कार्य करने का भरोसा दिया है।

डीडीसी ने बताया कि सड़क निर्माण में उपयोग के लिए प्लास्टिक कचरे को निर्धारित आकार में छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित किया जा रहा है। इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में प्रसंस्करण का कार्य चल रहा है। उन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण योग्य तैयार करें, ताकि जल्द इसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जा सके। निरीक्षण के दौरान निदेशक आशुतोष कुमार, किशनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पिंकी कुमारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक सहित स्वच्छता विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति की दिशा में बिहार की पहल महत्वपूर्ण : विजय चौधरी

पटना,एजेंसी। बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नई दिल्ली में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। पटना में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में विजय चौधरी ने कहा कि नदियों में गाद जमा होना उनकी बदहाली और बाढ़ की भयावहता के प्रमुख कारणों में से एक है। बिहार सरकार पिछले डेढ़ दशक से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति की मांग कर रही थी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गाद की समस्या की गंभीरता की पहचान वर्ष 2011-12 में हुई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। उनके आमंत्रण पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को बक्सर से फरक्का तक हवाई यात्रा कराकर गंगा में गाद जमा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा भी दिलाया गया था। विजय चौधरी ने बताया कि वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के समक्ष भी गाद प्रबंधन नीति की आवश्यकता और फरक्का बराज के निर्माण के बाद बिहार के हिस्से में गाद जमा होने की अनियंत्रित गति का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद पहली बार गाद प्रबंधन को लेकर विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022 में तलछट



प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रस्तावित किया गया। इस पर राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए, लेकिन इसे अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने हाल ही में 'बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन और गाद प्रबंधन नीति-2026' तैयार की है। इसमें गाद के निस्तारण की प्रक्रिया और व्यावहारिक उपाय शामिल किए गए हैं। इसी नीति के आधार पर तीन नवंबर को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि इस पहल से नदियों से गाद निकालने में मदद मिलेगी, जिससे उनका पुनर्जीवन होगा और बाढ़ की भयावहता कम की जा सकेगी। इसके अलावा सड़कों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों में मिट्टी भराई के लिए निकाली गई गाद का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे किसानों की उपजाऊ मिट्टी की कटाई पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

एक नजर

महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए श्रीलंका की 14 सदस्यीय टीम घोषित



नई दिल्ली,एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली आगामी आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी-2026 के लिए श्रीलंका ने 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान चमारी अटापट्टू की गैरमौजूदगी में हर्षिता समरविक्रमा टीम की कमान संभालेंगी। आईसीसी वेबसाइट के अनुसार टीम में दो प्रमुख खिलाड़ियों विष्मी गुणरत्ने और निलाक्षिका सिल्वा की वापसी हुई है। इसके अलावा तेज गेंदबाज माल्की मदारा को भी टीम में जगह मिली है। सत्या संदीपनी को भी छह साल बाद टी-20 टीम में वापसी का मौका मिला है। उन्होंने अब तक श्रीलंका के लिए केवल एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला है। श्रीलंका उन पांच पूर्ण सदस्यों (आयरलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के अलावा) में से एक है, जो टूर्नामेंट के नए फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। इस नए फॉर्मेट में 10 टीमें शामिल हैं, जबकि पिछले संस्करण में केवल 5 टीमें थीं। महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के इस संस्करण में टीमों की संख्या पांच से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। श्रीलंका के अलावा आयरलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पांच पूर्ण सदस्य देशों के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, मेजबान संयुक्त अरब अमीरात और मौजूदा चैंपियन थाईलैंड शामिल हैं। टूर्नामेंट में टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और संयुक्त अरब अमीरात हैं, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे हैं। यह टूर्नामेंट 12 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका अपने पहले मैच में 12 नवंबर को आयरलैंड का सामना करेगी। श्रीलंका की 14 सदस्यीय टीम हर्षिता समरविक्रमा (कप्तान), कवीशा दिलहारी (उपकप्तान), संजना काविंदी, इमेशा दुलानी, हासिनी परेरा, विष्मी गुणारत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना, सत्या संदीपनी, रश्मिका सेववंडी, सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मल्की मदारा, चेतना विमुक्ति।

रॉयल एनफील्ड ने हिमालय में आइस हॉकी विकास कार्यक्रम के चौथे सत्र की घोषणा की

नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड ने हिमालय में आइस हॉकी के विकास के लिए अपने चौथे सत्र की घोषणा की है। इस पहल के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और गोलरक्षकों को प्रशिक्षण देकर जमीनी स्तर पर खेल की मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी। इस सत्र की शुरुआत 9 से 13 नवंबर तक लेह के नॉवांग दोरजे स्तोब्दान (एनडीएस) स्टेडियम में पहली बार आयोजित होने वाले विशेष गोलरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से होगी। अंतरराष्ट्रीय गोलरक्षक प्रशिक्षक मैट डार्लो लद्दाख और स्पीति के गोलरक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। निर्णायकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ से प्रमाणित पीटर गेबी संभालेंगे, जिन्हें इस खेल में चार दशक से अधिक का अनुभव है। इसके अलावा लेह, देहरादून और गुरुग्राम में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिसंबर से फरवरी, 2027 तक जमीनी स्तर पर 'लर्न टू प्ले' कार्यक्रम चलाया जाएगा। सत्र के प्रमुख आकर्षणों में रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग (आरईआईएचएल) और हिमाचल प्रदेश के काजा में होने वाला स्पीति कप शामिल हैं। दोनों प्रतियोगिताएं अपने आयोजन के चौथे वर्ष में प्रवेश करेंगी। आरईआईएचएल का आयोजन लद्दाख प्रशासन और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के सहयोग से होगा, जबकि स्पीति कप आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल-स्पीति के साथ आयोजित किया जाएगा। आइशर ग्रुप फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक बिदिशा डे ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस खेल से जुड़ी स्थानीय विशेषज्ञता को मजबूत करना है, ताकि यहां के खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों को विश्व-स्तरीय कौशल से लैस किया जा सके। इससे वैश्विक विंटर स्पोर्ट्स के मंच पर भारत के भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो रही है। रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग और स्पीति कप के 2026 संस्करण में पुरुष और महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। स्पीति कप में अंडर-18 लड़कों का वर्ग भी शामिल था। आरईआईएचएल में पुरुषों की 11 और महिलाओं की पांच टीमों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में हुमास वॉरियर्स और महिला वर्ग में शाम ईगल्स ने खिताब जीता। स्पीति कप में सेंट्रल जोन ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए, जबकि शाम जोन अंडर-18 वर्ग का विजेता बना था।

अफगानिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम घोषित

नई दिल्ली। जिम्बाब्वे ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएआई) में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। नियमित कप्तान रिचर्ड नगारवा के चोटिल होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में ब्रायन बेनेट टीम की कप्तानी संभालेंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट के अनुसार रिचर्ड अभी भी पीठ की चोट से उबर रहे हैं और टीम से बाहर हैं। तेज गेंदबाज तनाका चिवंगा भी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी शामिल हैं जो उस टीम का हिस्सा थे, जिसने जून में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में बांग्लादेश को एक पारी और 85 रनों से हराकर जिम्बाब्वे की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की थी। बल्लेबाजी विभाग में अनुभवी ब्रेंडन टेलर और क्रेग इरविन के साथ इनोसेंट काइया, बेन करन, तादिवानाशे मरुमानी और वेस्ली मधेवेरे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। अनुभवी लेग-स्पिनर ग्रीम क्रेमर भी टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं। कुंडई मातिगिमु और विंसेंट मासेकेसा की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा ऑलराउंडर एंटम नकवी को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अब जिम्बाब्वे की ओर से खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पात्रता संबंधी मानदंड पूरे कर लिए हैं। तेज गेंदबाजी विभाग में ब्लेसिंग मुजरबानी प्रमुख गेंदबाज होंगे। उनके साथ ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, कुंडई मातिगिमु और पहली बार टीम में शामिल किए गए अर्नेस्ट मासुकु को मौका दिया गया है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी ग्रीम क्रेमर, विंसेंट मासेकेसा और वेलिंगटन मसाकाद्जा संभालेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीमब्रायन बेनेट (कप्तान), एंटम नकवी, बेन करन, ब्लेसिंग मुजरबानी, ब्रैड इवांस, ब्रेंडन टेलर, क्रेग इरविन, ग्रीम क्रेमर, इनोसेंट काइया, अर्नेस्ट मासुकु, कुंडई मातिगीमु, न्यूमैन न्यामहुरी, तदिवनाशे मारुमानी, तफादजवा सिगा, विंसेंट मासेकेसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे।

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया, कोहली ने जड़ा अर्धशतक

ऑकलैंड,एजेंसी। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया। ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। इसके बाद बारिश के कारण भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम (डीएलएस) के तहत जीत के लिए 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। भारतीय टीम ने 22.4 ओवर में पांच विकेट पर 143 रन बनाते हुए इसे हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच अगला वनडे सात नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा।



भारत की जीत के नायक स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रहे, जिन्होंने 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरे। हालांकि, बारिश के कारण मुकाबले में दो बार रुकावट आई। पहली बार 10.5 ओवर के बाद खेल रोका गया। बारिश थमने पर मैच को 40 ओवर का कर दिया गया और भारत के सामने 167 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई। खेल फिर शुरू होने पर भारतीय टीम को 32 ओवर में 143 रन बनाने का लक्ष्य मिला। इसके बाद विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का 80वां अर्धशतक रहा। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। भारत को 114 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल 56 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी 51 गेंदों में 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।अक्षर पटेल बिना खाता खोले आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 15 रन का योगदान दिया। अंत में नमन धीर ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। केएल राहुल तीन और नमन धीर पांच रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने तीन विकेट लिए, जबकि काइल जैमीसन और नाथन स्मिथ को एक-एक सफलता मिली।

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही और 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से केवल पांच बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। टिम सेफर्ट ने 43 गेंदों में 38 रन बनाए। ब्लेयर टिकनर ने निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में एक चौके और चार छक्कों के सहारे 34 रन जोड़े। ग्लेन फिलिप्स ने 51 गेंदों में 30 और डेरिल मिचेल ने 41 गेंदों में 28 रन बनाए। जैकब डफी 15 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं विल यंग और हेनरी निकोल्स ने नौ-नौ रन बनाए। टॉम लाथम तीन, कप्तान मिचेल सैंटनर चार, नाथन स्मिथ एक और काइल जैमीसन एक रन बनाकर आउट हुए।

मध्य प्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों का कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली। एशियन हॉकी फेडरेशन (एएचएफ) ने मध्य प्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नए हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भारत, जापान, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें खिताब के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगी। यह टूर्नामेंट भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पिछले महीने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मेजबान भारत की टीम इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा लेगी। भारतीय टीम अब तक 2016, 2023 और 2024 में यह खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम की नजर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने और अपने खिताबों की संख्या बढ़ाने पर होगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेंगी। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। टूर्नामेंट के पहले दिन 19 नवंबर को चीन और थाईलैंड के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ करेगा। इसी दिन मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। इसके बाद मेजबान भारतीय टीम 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान का सामना करेगी। 20, 23 और 26 नवंबर को विश्राम दिवस (रेस्ट डे) तय किए गए हैं। 27 नवंबर को पांचवें और छठे स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच होगा, जिसके बाद दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 28 नवंबर को ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल के साथ समाप्त होगा, जिसमें पदक जीतने वाली तीन टीमों का फैसला होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, 'मध्य प्रदेश महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026, एशिया में महिला हॉकी की बढ़ती ताकत का जश्न मनाने का एक शानदार मौका होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे खुशी है कि भोपाल छह मजबूत टीमों की मेजबानी करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी भारतीय टीम एशियाई खेलों में मिली हालिया सफलता को आगे बढ़ाएगी और अपने खिताब का बचाव करेगी।

माई भारत पोर्टल पर शुरू हुई 'खेलो भारत' क्विज, 20 नवंबर तक चलेगी

नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने बुधवार को माई भारत पोर्टल पर खेलो भारत: विनिर्माण से लेकर पदक जीतने तक की यात्रा पर प्रश्नोत्तरी शुरू की है। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य देश के खेल पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना, घरेलू खेल सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा देना, एशियाई खेल-2026 और एशियाई पैरा खेल-2026 में भारत की उपलब्धियां तथा सरकार की पहल के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।

खेल मंत्रालय के अनुसार यह प्रश्नोत्तरी 20 नवंबर तक चलेगी, जिसे आम लोगों, विद्यार्थियों, युवाओं, पेशेवरों और खेल प्रेमियों को खेल सामग्री विनिर्माण एवं नवाचार से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तक, भारत के बढ़ते खेल पारितंत्र की जानकारी प्राप्त करने और इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी में खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसके लिए 1,856.67 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित है। योजना का उद्देश्य भारत में घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के दो घटक प्रोत्साहन और हस्तक्षेप हैं। इनमें निवेश सहायता, विनिर्माण क्षेत्र, मौजूदा क्लस्टर, उत्पादन प्रोत्साहन, प्रमाणन एवं परीक्षण, अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, निर्यात में बढ़ोतरी लाना तथा भारतीय खेल सामग्री निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत बनाना है। प्रश्नोत्तरी में जापान में आयोजित एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल में भारत की भागीदारी से संबंधित विषय भी शामिल हैं। प्रश्नोत्तरी में कोई आयु सीमा नहीं है और सभी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। इसमें लिंग, शैक्षणिक योग्यता या राज्य के आधार पर कोई विशेष पात्रता प्रतिबंध नहीं है। प्रतिभागियों को 20 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने से पहले उन्हें माई भारत पोर्टल पर उपलब्ध संदर्भ सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी के परिणामों के आधार पर शीर्ष 100 प्रतिभागियों को फिट इंडिया की ओर से उपहार सामग्री दी जाएगी। समान अंक मिलने की स्थिति में कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली द्वारा विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी के बाद प्रतिभागी सही उत्तर भी देख सकेंगे।

रणजी मैच : रोहन राजभर के शतक और लोमरोर के 97 रन से राजस्थान ने हिमाचल को दिया 447 रन का बड़ा लक्ष्य

धर्मशाला,एजेंसी। एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलीट मुकाबले में राजस्थान ने हिमाचल प्रदेश के सामने 447 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। मैच के तीसरे दिन राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी आठ विकेट पर 521 रन बनाकर घोषित की। जवाब में हिमाचल प्रदेश ने दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में चार विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं। हिमाचल को जीत के लिए अभी 364 रन की जरूरत है और उसके छह विकेट शेष हैं। राजस्थान की दूसरी पारी में रोहन राजभर ने शानदार 140 रन की पारी खेली। उन्होंने 263 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और एक छक्का लगाया। महिपाल लोमरोर शतक से चूक गए और 97 रन पर आउट हो गए। वहीं कार्तिक शर्मा ने 59 गेंदों में 63 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल रहे। करण लांबा ने भी 26 रन का योगदान दिया। पहली पारी में राजस्थान की टीम हिमाचल के गेंदबाजों के सामने महज 78 रन पर सिमट गई थी।

इससे पहले हिमाचल प्रदेश की पहली पारी 40 ओवर में 153 रन पर समाप्त हुई थी। टीम की ओर से अंकुश बैंस ने 78 गेंदों में 56 और पुखराज मान ने 50 गेंदों में 42 रन बनाए। वैभव कल्टा ने 15 और जितेंद्र राणा ने 10 रन का योगदान दिया। राजस्थान की ओर से साहिल धीवान ने पांच विकेट लेकर हिमाचल की बल्लेबाजी को झटका दिया, जबकि अंकित चौधरी ने तीन और दानिश भांभू ने दो विकेट हासिल किए। राजस्थान की पहली पारी में



हिमाचल के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अभिषेक कुमार ने 9.3 ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके। जितेंद्र राणा ने 22 रन देकर तीन और अर्पित गुलेरिया ने 14 रन देकर एक विकेट हासिल किया। राजस्थान की टीम पहली पारी में 30.3 ओवर में 78 रन पर ढेर हो गई थी। दूसरी पारी में राजस्थान के बल्लेबाजों ने शानदार वापसी करते हुए हिमाचल के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। राजस्थान ने इसके बाद पारी 521 रन पर घोषित कर हिमाचल के सामने बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब मुकाबले के अंतिम दिन हिमाचल के बल्लेबाजों के सामने जीत के लिए बड़ा लक्ष्य हासिल करने के साथ विकेट बचाने की चुनौती होगी।

डब्ल्यूपीएल-2027 का कार्यक्रम घोषित, वडोदरा और मुंबई में होंगे मुकाबले

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के पांचवें संस्करण का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह संस्करण 14 जनवरी से 7 फरवरी, 2027 तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट वडोदरा और मुंबई में आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 11 मैच खेले जाएंगे। डब्ल्यूपीएल के अनुसार नए सीजन की शुरूआत 14 जनवरी, 2027 को वडोदरा में होगी। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का मुकाबला पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) से होगा। वडोदरा में 11 मैच खेले जाएंगे, जहां पांचों टीमें खिताब जीतने की दौड़ में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके बाद मुकाबले मुंबई में होंगे, जहां क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 26 जनवरी से बाकी 11 मैच खेले जाएंगे। लीग चरण 3 फरवरी तक चलेगा, जिससे यह तय होगा कि प्लेऑफ में कौन सी टीमें पहुंचेंगी। खिताब की दौड़ पांच फरवरी को 'एलिमिनेटर मुकाबले' के साथ और रोमांचक हो जाएगी। इसमें पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी। लीग चरण में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जो 7 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी 22 मैच (प्लेऑफ सहित) शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। इस तरह दो



अलग-अलग जगहों पर पांच टीमों के बीच होने वाले पांचवें संस्करण में प्रतिष्ठित खिताब के लिए एक और रोमांचक रेस देखने को मिलेगी।

घोषित कार्यक्रम के अनुसार 14 जनवरी को पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। इसके बाद 15 जनवरी को गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स, 16 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 17 जनवरी को यूपी वॉरियर्स का सामना मुंबई इंडियंस से तथा 18 जनवरी को गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद 19 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वारियर्स, 20 जनवरी को गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा, 21 जनवरी को यूपी वारियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 22 जनवरी को गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 23 जनवरी दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 24 जनवरी को यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स वडोदरा, 26 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स, 28 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वारियर्स, 29 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 30 जनवरी को मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, 31 जनवरी यूपी वारियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एक फरवरी मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2 फरवरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, 03 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स के बीच मुकाबला होगा। पांच फरवरी को एलिमिनेटर मुकाबला और 7 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा।

महिला टी20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली प्रेमा रावत को सीएयू सचिव महिम वर्मा ने दी बधाई

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व उपाध्यक्ष एवं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) के सचिव महिम वर्मा ने महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी प्रेमा रावत की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रेमा रावत ने जो उपलब्धि हासिल की है, उस पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को गर्व है। उत्तराखंड की 24 वर्षीय प्रेमा रावत ने सीनियर वूमेंस टी-20 ट्रॉफी में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को आकर्षित किया। दो नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में प्रेमा ने महज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए महिला टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पाकिस्तान की फातिमा सना (15 गेंद में पचासा) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अपनी इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। केवल बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी उन्होंने 4 ओवर में मात्र 12 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। महिम वर्मा ने प्रेमा को बधाई देते हुए कहा कि 14 गेंदों में रिकॉर्ड अर्धशतक बनाना और गेंद व बल्ले दोनों से कमाल दिखाना उनकी अद्भुत क्षमता और कड़ी मेहनत का नतीजा है। प्रेमा एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो सुदूर क्षेत्र से आकर आज विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड हमेशा से ऐसे युवा खिलाड़ियों को तराशने के लिए काम करता रहा है। हाल ही में हुए उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में उनके शानदार प्रदर्शन से साफ था कि वे बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेमा आगे भी इसी तरह नए रिकॉर्ड बनाएंगी और भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन करेंगी।

उत्तराखंड के एक दूर-दराज और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रेमा की प्रतिभा को निखारने में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीएयू ने प्रेमा की काबिलियत को शुरुआती दिनों में ही पहचाना और उन्हें हर संभव सुविधाएं, आधुनिक कोचिंग और सही मार्गदर्शन प्रदान किया। हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग ने भी उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीएल के जरिए मिले शानदार अनुभव और मैच एक्सपोजर के दम पर ही वे आज उत्तराखंड की टीम के लिए ऐसा मैच-विनिंग प्रदर्शन कर पा रही हैं। प्रेमा भारत के लिए अब तक सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 7 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलती हैं। मुकाबले की बात करें तो प्रेमा रावत की 50 रन की नाबाद पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम ने 20 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद सिर्फ आठ विकेट खोकर 98 रन ही बना पाई। इस तरह उत्तराखंड ने यह मैच 89 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था।

एक नजर

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने चुनावी हार के लिए ईरान युद्ध को ठहराया जिम्मेदार

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी हार के बाद ईरान युद्ध समाप्त करने और इजराइल के साथ अमेरिका के संबंधों की समीक्षा करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के चुनाव में समर्थन करने वाले कई मतदाताओं ने 2026 के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में मतदान किया। वेंस के मुताबिक, मतदाताओं की नाराजगी की प्रमुख वजह ईरान युद्ध और उससे जुड़ी नीतियां रहीं। वेंस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की हार से दो प्रमुख सबक मिले हैं। उन्होंने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप-वेंस को 2024 में वोट देने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले मतदाताओं से पूछा गया था कि वे किन परिस्थितियों में फिर से रिपब्लिकन पार्टी के साथ आ सकते हैं। वेंस के अनुसार, इन मतदाताओं के जवाबों में चार मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। इनमें ईरान युद्ध समाप्त करना, महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत पर ध्यान देना, 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति को प्राथमिकता देना तथा इजराइल के साथ अमेरिका के संबंधों में बदलाव करना शामिल है। उपराष्ट्रपति ने ईरान संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकालने की पैरवी करने वाली एक महिला की राजनीतिक सलाह का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सलाह सही साबित हुई। वेंस की इस टिप्पणी को उन लोगों की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है, जो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्षधर रहे हैं। इनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी बताया जा रहा है। वेंस ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजह युद्ध है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पिछली रात इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि, ट्रंप ने युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को चुनावी नुकसान का एक कारण माना था, लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के फैसले का बचाव भी किया था।

एथेंस विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा, छात्र सभा पर हमला, तीन घायल

एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस स्थित विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को छात्र सभा पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने धावा बोला, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। हेलमेट पहने कुछ लोगों के समूह ने सभा को निशाना बनाया। ग्रीस की आपातकालीन चिकित्सा सेवा और सरकारी समाचार एजेंसी 'एथेंस न्यूज एजेंसी' ने यह जानकारी दी। घायलों को एथेंस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। चिकित्सा सेवा के अनुसार, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हमला किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी। ग्रीस के शिक्षा मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा शैक्षणिक समुदाय का अपमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब ग्रीस में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र और शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों छात्रों और शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर शिक्षा के लिए सरकारी बजट बढ़ाने, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और कक्षाओं में भीड़ कम करने की मांग की थी।

सर्बिया के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने सर्बिया के लिए सदस्यता वार्ता को आगे बढ़ाने की नई उम्मीद जताई है। ईयू का कहना है कि यदि चुनाव में जीत हासिल करने वाला छात्र नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने और संस्थागत सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हो, तो सर्बिया की सदस्यता प्रक्रिया को नई गति मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्र नेतृत्व वाले विविध विपक्षी आंदोलन की चुनावी सफलता पश्चिमी बाल्कन के इस प्रभावशाली देश के साथ ईयू के संबंधों को नए सिरे से व्यवस्थित करने का अवसर दे सकती है। यूरोपीय संघ की विस्तार आयुक्त मार्टा कोस ने सदस्यता विस्तार पर तैयार रिपोर्ट के बारे में ईयू सांसदों को जानकारी देते हुए कहा कि सर्बिया के पास नई शुरुआत करने का मौका है। उन्होंने कहा कि नई सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के साथ यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में जरूरी कदम उठा सकती है। कोस के मुताबिक, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार बनने पर सर्बिया की सदस्यता प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में उसकी ईयू सदस्यता में अभी कई साल लगने की संभावना है। यूरोपीय आयोग की विस्तार रिपोर्ट में अन्य देशों की सदस्यता संभावनाओं का भी आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मोंटेनेग्रो 2028 में यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनने की राह पर है। वहीं, अल्बानिया और मोल्दोवा के 2029 में संघ में शामिल होने की संभावना जताई गई है।

पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ और अस्थिरता फैलाने का आरोप

प्रीटोरिया। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन और प्रशिक्षण देने तथा सीमा पार से लड़ाकों की घुसपैठ कराकर देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के समाचार पोर्टल 'इंडिपेंडेंट ऑनलाइन' (आईओएल) की एक रिपोर्ट में इन आरोपों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत, ईरान और कई पश्चिमी देश भी पहले पाकिस्तान में सक्रिय तत्वों पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगा चुके हैं। तालिबान के मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों ने नूरिस्तान प्रांत के कामदेश जिले में चलाए गए अभियान के दौरान 41 आतंकवादियों को मार गिराया और 62 अन्य को गिरफ्तार किया। तालिबान ने दावा किया कि ये लड़ाके इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों के सदस्य थे और उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों का समर्थन हासिल था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने 29 सितंबर को जारी बयान में कहा था कि कामदेश जिले में सशस्त्र विरोधियों के खिलाफ अभियान पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार ये लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पार से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के समर्थन से अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने घुसपैठ की इस कोशिश को पाकिस्तानी सेना के 'प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और सहयोग' से अंजाम देना बताया। तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी जमीन पर लड़ाकों की भर्ती करने और उन्हें हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियां अफगानिस्तान में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान पर पहले भी हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को संरक्षण देने के आरोपों का जिक्र किया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के दौरान तत्कालीन अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल माइक मुलेन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की 'वास्तविक शाखा' बताया था।

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत, संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण, राष्ट्रपति ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार किया

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी मतदाताओं ने मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। मतगणना के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सीएनएन और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेट्स ने अमेरिका संसद (कांग्रेस) पर फिर नियंत्रण हासिल कर लिया है। कांग्रेस के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की 425 सीटों के लिए लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेट्स ने 224 सीटों पर जीत हासिल की है। रिपब्लिकन को 129 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अब तक के नतीजों में डेमोक्रेट्स ने बहुमत का आंकड़ा 218 पार कर लिया है। बाकी अधिकांश सीटों पर भी डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।



सीएनएन और सीबीएस न्यूज चैनल की चुनाव डेस्क से प्रसारित समाचारों में बताया गया है कि इसके अलावा 100 सदस्यीय सीनेट (उच्च सदन) की 35 सीट और 36 गवर्नर के पदों के नतीजे भी आने लगे हैं। इनमें से 33 सीटों पर नियमित रूप से 6 साल के कार्यकाल के लिए मतदान हुआ है। बाकी की दो सीटें (ओहायो और फ्लोरिडा) विशेष चुनाव के तहत हैं। ये सीटें जेडी वेंस के उपराष्ट्रपति बनने के कारण और मार्को रुबियो के विदेश मंत्री बनने के कारण के दिए गए इस्तीफे से खाली हुई थीं। सीनेट की शेष 65 सीटों पर इस बार चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट के केवल एक-तिहाई सदस्यों के लिए ही हर दो साल में चुनाव कराए जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन गढ़ माने जाने वाले कई राज्यों में जीत दर्ज कर सात सीटों का फायदा हासिल किया। सदन में उनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की सीट घटकर 42 हो गई है। दोनों समाचार चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने उन जगहों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां दो साल पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने आसानी से जीत हासिल की थी। डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों पर शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इससे उन्हें ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो सालों में उन पर लगाम लगाने के लिए काफी ताकत मिल गई है। ट्रंप ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से कहा कि वह नतीजों को स्वीकार करते हैं। इससे फिलहाल उन सवालों पर विराम लग गया है कि क्या वे नतीजों को चुनौती देंगे। फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे रिपब्लिकन पार्टी की पराजय को 'अपने ऊपर लगे झटके' के तौर पर नहीं देखते हैं।

बांग्लादेश की राजधानी में औद्योगिक अशांति, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, झड़प, 100 घायल, 40 गिरफ्तार

ढाका। देश की राजधानी के मीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों की 30,000 टका न्यूनतम वेतन करने की मांग को लेकर तीन दिन से चल रहा आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच दिनभर तीखी झड़पें हुईं। शाम होते-होते धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि इन झड़पों में 100 लोग घायल हुए हैं। घायलों में पुलिस कर्मचारी भी हैं। अशांति फैलाने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा उद्योग कर्मचारियों और मजदूरों ने सरकार के आंदोलन के पीछे किसी राजनीतिक उकसावे या बड़ी साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई के चलते वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। पुलिस ने अशांति भड़काने के आरोप में देररात 40 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी शोएब इस्लाम ने कहा कि तोड़फोड़ या हिंसा में मजदूरों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम मजदूर किसी भी तरह की तोड़फोड़ में शामिल नहीं हैं। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह पुलिस का काम है कि वह इस पर कार्रवाई करे।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी वजह के हमला किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके साथियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है, तो मजदूर इसका विरोध करेंगे। एक अन्य मजदूर शेफली बेगम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि इन प्रदर्शनों के पीछे बाहरी समूहों का हाथ है। उन्होंने कहा, 'हमें किसी ने उकसाया नहीं है। हम अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शमीम ने कहा कि अगर सरकार मांगी गई न्यूनतम वेतन राशि की घोषणा कर दे, तो ये प्रदर्शन तुरंत खत्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'अगर सरकार 30,000 टका न्यूनतम वेतन की घोषणा कर देती है, तो सभी मजदूर अपनी फैक्ट्रियों में लौट जाएंगे और कोई भी सड़क पर नहीं रहेगा।' वहीं, कानून लागू करने वाले अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों में ऐसे लोग घुस आए हैं, जिनका मजदूरों की वेतन मांगों से कोई लेना-देना नहीं है। ढाका रेंज के डीआईजी मो. मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि ढाका, मीरपुर, गाजीपुर और नारायणगंज में हुई अशांति के सिलसिले में पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है।

नेपाल आये भारतीय विदेश सचिव ने की द्विपक्षीय वार्ता, पीएम बालेन्द्र शाह के भारत भ्रमण के एजेंडे पर हुई चर्चा

काठमांडू। नेपाल दौरे पर आये भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने समकक्ष अमृत राई से द्विपक्षीय वार्ता की है। इस वार्ता के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के भारत भ्रमण के एजेंडे पर चर्चा हुई है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि बुधवार को हुई बातचीत का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संदर्भ में आगे बढ़ाई जाने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें होंगी। इसके लिए विस्तृत कार्यसूची तैयार की गई है और इस पर नेपाली विदेश सचिव के साथ चर्चा करने के लिए वे उत्सुक हैं।भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि भोटेकोशी बाढ़ से क्षतिग्रस्त नेपाल के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है।

बुधवार को नेपाल की यात्रा के दौरान विदेश सचिव अमृत बहादुर राय सहित नेपाली प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में मिस्री ने कहा कि बाढ़ से नेपाल के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और भारत उसके पुनर्निर्माण में मदद करने का इच्छुक है। मिस्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के साथ-साथ दोनों पक्षों की ओर से शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों के क्रियान्वयन में भी प्रगति हुई है। इसके लिए दोनों पक्षों के अधिकारी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच एक विशिष्ट संबंध है और दोनों देश सुख-दुख, हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साझेदार रहे हैं। मिस्री ने कहा कि भोटेकोशी बाढ़ के बाद उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में दोनों देशों के संबंधों को व्यवहार में प्रदर्शित करने का अवसर मिला। भारत ने नेपाल को सहायता उपलब्ध कराई है, लेकिन इस आपदा से नेपाल के बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और तबाही को भी भारत समझता है।

उन्होंने कहा कि नेपाल में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर भारत आवश्यक सहायता और परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है। मिस्री ने कहा कि इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। नेपाल के नेतृत्व के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी के साथ आगे चर्चा करने के लिए हम इच्छुक हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग जारी रहने का विश्वास व्यक्त किया।

बैंकॉक में भारतीय समुदाय ने मनाई भव्य दिवाली, भारत-थाईलैंड मैत्री को मिला नया आयाम

बैंकॉक,एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय ने भव्य समारोह आयोजित कर दिवाली का पर्व मनाया। इसमें थाई सरकार के अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों, आध्यात्मिक गुरुओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया। फेयरमोंट बैंकॉक सुखुमवित में आयोजित 'ग्रैंड दिवाली सेलिब्रेशन एंड वेलकम रिसेप्शन 2026' के जरिए भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव तथा आपसी मित्रता को रेखांकित किया गया।

'सामूहिक शक्ति, साझा दृष्टि' (कलेक्टिव स्ट्रेंथ, शेयर्ड विजन) की थीम पर आयोजित इस समारोह का उद्देश्य थाईलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाने के साथ थाई समाज और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके संबंधों को मजबूत करना था। कार्यक्रम में थाईलैंड के धार्मिक मामलों के महानिदेशक जेट्सादा चीवाचावानकुल, संस्कृति मंत्रालय की सहायक स्थायी सचिव उरुसाया इंत्रासुक्सरी, भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल और मालदीव के राजदूत फुवाद थोफीक सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। प्रयागराज-लखनऊ स्थित श्री तीर्थराज आध्यात्मपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी श्री अभिराम आचार्य जी महाराज और ट्रेंड मार्बल एंड डिजाइन कंपनी की अध्यक्ष एवं सीईओ जूलिंग पात्रा चिराथिवात भी मौजूद रहीं। स्वीडन, रूस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, श्रीलंका, लाओस और केन्या के राजनयिक प्रतिनिधियों तथा अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की भागीदारी ने समारोह को व्यापक स्वरूप दिया।



दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजक कार्यक्रमों ने उत्सव का माहौल बनाया। प्रसिद्ध कलाकार पायल वखारिया की लाइव संगीत प्रस्तुति समारोह का विशेष आकर्षण रही। इस अवसर पर भारतीय समुदाय के विकास और थाई समाज के साथ उसके जुड़ाव को मजबूत करने में योगदान देने वाले संगठनों, कारोबारियों, प्रायोजकों और लोगों को भी सम्मानित किया गया।

बालेन्द्र सरकार अपनी ही पार्टी के निर्देशों की कर रहे अनदेखी, आंतरिक विवाद में घिरी आरएसपी

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल की बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में रही सरकार द्वारा अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के द्वारा दिए गए निर्देशों और नीतियों की पालन करने में आनाकानी और अनदेखी करने से सरकार और पार्टी के बीच दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। सत्तारूढ़ आरएसपी ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बार-बार अपनी चिंताएं रखी हैं और कई बार चेतावनी के साथ निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन पार्टी की इन मांगों और हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर अनसुना किया गया है। पार्टी ने लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ मानी जाने वाली गतिविधियों पर चिंता जताई है। हालांकि, पीएम शाह ने पार्टी के इन निर्देशों की हमेशा ही अनदेखी की है।

गत 13 जुलाई को मीडिया संस्थानों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास के सामने वाहन खड़े कर रास्ता बाधित किया गया था। बताया गया कि इस घटना में सरकार से जुड़े लोग शामिल थे। मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर वाहन खड़े किए जाने की खबरें सामने आने के तुरंत बाद आरएसपी के महासचिव बिपिन आचार्य ने बयान जारी कर सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया। उन्होंने मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर वाहन खड़े कर रास्ता रोकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। ऑनलाइन खबर, हिमालय टेलीविजन और कान्तिपुर जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर कथित तौर पर सरकार के करीबी लोगों ने वाहन खड़े किए थे। प्रधानमंत्री शाह के करीबी लोगों ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह पासपोर्ट विभाग के सामने गणेश नेपाली द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद मीडिया संस्थानों की खुले स्थानों पर पार्किंग के समर्थन में अपनाई गई स्थिति के जवाब में किया गया था।

प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने जहां रास्ता बाधित करने की कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं पार्टी ने इसका



विरोध किया। आचार्य ने कहा कि स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की जीवनरेखा है। बयान में कहा गया, 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इसलिए पार्टी प्रेस को डराने-धमकाने के उद्देश्य से की गई इन और ऐसी किसी भी अन्य कार्रवाई की निंदा करती है। आरएसपी ने कहा कि राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को निर्भीक होकर काम करने के लिए आवश्यक वातावरण को कमजोर करने के उद्देश्य से की जाने वाली संदिग्ध और अस्पष्ट गतिविधियां लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन हैं। मीडिया के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जताते हुए आरएसपी ने सरकार से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। बयान में कहा गया, 'हम नेपाल सरकार, गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों का गंभीर ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि वे मीडिया संस्थानों की भौतिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की तत्काल पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई करें। पार्टी के हस्तक्षेप के बावजूद पीएम बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटना की जांच करने या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बेन और गृह मंत्री सुदन गुरुङ के करीबी लोग भी कथित तौर पर मीडिया संस्थानों के रास्ते रोकने के लिए वाहन खड़े करने में शामिल थे। मीडिया संस्थानों द्वारा वाहन मालिकों की पहचान कर अधिकारियों को जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पिछले सप्ताह भी यही स्थिति दोहराई गई, जब सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया संस्थानों में प्रवेश कर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। नेपाल प्रेस के पत्रकार विश्वमणि सुबेदी को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने नया पत्रिका के कार्यालय में भी बिना गिरफ्तारी वारंट के उसके एक पत्रकार को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी।

30 अक्टूबर को पुलिस ने मोटिवेट न्यूज के संपादक शोभराज बराल और डीएनए खबर के प्रधान संपादक धीरज बस्नेत को गिरफ्तार किया। इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया और भी गैरजिम्मेदाराना रही। प्रधानमंत्री सचिवालय ने मामले से शाह को अलग करते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारों की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। वहीं, पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि पत्रकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हिरासत में लिया गया था। आरएसपी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी और सुरक्षा कर्मियों के मीडिया संस्थानों में प्रवेश पर तत्काल आपत्ति जताई। 30 अक्टूबर को पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट जारी कर पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। पार्टी ने सचिवालय की आपात बैठक भी बुलाई। बैठक में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराते हुए सरकार को घटना की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक के निर्णय में कहा गया, '30 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन द्वारा मीडिया क्षेत्र में की गई कुछ गतिविधियां, जो एक मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, संविधान और पार्टी के मूल आदर्शों के विपरीत हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार को निर्देश देती है कि गैरजिम्मेदाराना आदेश जारी करने वालों की तत्काल पहचान कर जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक बार फिर सरकार ने पार्टी के निर्देश की अनदेखी की। निर्णय पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बेन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को हल्के में लिया। सरकार ने पत्रकारों की गिरफ्तारी या मीडिया कार्यालयों में सुरक्षा कर्मियों के प्रवेश की जांच किए बिना ही ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। 13 अक्टूबर को आचार्य ने बयान जारी कर सरकार से पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक विवादित बिचौलिए के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग की गंभीरता को समझने और जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। बयान में कहा गया, 'हमें विश्वास है कि संबंधित सरकारी एजेंसियां शीघ्र ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच करेंगी। हम सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया में पार्टी की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं। लेकिन इस अपील का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और सरकार ने पत्रकारों की धड़पकड़ करने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और अन्य पदाधिकारी सरकार के रवैये से नाराज दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने कहा कि पार्टी के निर्देशों की अनदेखी करना सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। झा ने कहा कि यदि सरकार अपनी ही मनमानी करती रही और पार्टी निर्देशों का पालन नही किया तो पार्टी नेतृत्व को इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने पर मजबूर होना होगा।

एक नजर

सीबीएसई 12वीं बोर्ड में कैलकुलेटर की मांग पर हाई कोर्ट का केंद्र, सीबीएसई को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा। याचिका विशाल दुआ और अन्य अभिभावकों की ओर से अधिवक्ता नितिन मंगला के जरिये दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि गणित, अकाउंटेंसी और फिजिक्स जैसे विषयों में लंबी और जटिल गणनाएं करने में छात्रों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। इसके कारण छात्र परीक्षा में अपनी वैचारिक औरतार्किक समझ को बेहतर ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। याचिका में दलील दी गई कि सीबीएसई का कैलकुलेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना छात्रों के साथ अन्याय है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नवंबर, 2024 में खुद सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद दिसंबर, 2024 में इसे गवर्निंग बॉडी के समक्ष भी रखा गया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी बोर्ड ने इसे लागू नहीं किया। वर्तमान में सीबीएसई केवल 'डिस्कैलकुलिया' (गणितीय अक्षमता) से पीड़ित विशेष छात्रों को ही कैलकुलेटर की अनुमति देता है। याचिका में इस छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है। इस पर सीबीएसई के वकील ने कहा कि बोर्ड 204 विषयों की परीक्षा कराता है और इस नियम को बदलने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की समीक्षा और व्यापक लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी।

रामलीला मैदान के कार्यक्रम में अनुपस्थित युवा कांग्रेस के छह जिलाध्यक्षों समेत 26 नेता निलंबित

कोलकाता। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के कारण पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस ने छह जिलाध्यक्षों समेत कुल 26 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। संगठन की ओर से तीन नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता रोहन मित्र ने निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। निलंबित किए गए छह जिलाध्यक्षों में कूचबिहार के सुकमल बर्मन, जलपाईगुड़ी के नवीनेंदु मौलिक, उत्तर दिनाजपुर के मामून रेजा, पूर्व बर्दवान के मिथुन सरकार, उत्तर कोलकाता के अभिषेक गुप्ता और दक्षिण कोलकाता के इंद्रजीत मंडल शामिल हैं इसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बाबुल एसके और महासचिव पद पर कार्यरत कई नेताओं को भी निलंबित किया गया है। इनमें सफीकुल मल्लिक, कुणालकांति चौधरी, सुभारती चक्रवर्ती, तारिक अनवर शेख, साहिल नवाज, परीक्षित नाग, संजय खान, साजिद मोल्ला, मौ मंडल, तारिक अनवर, पुरब कुमार बसु, अर्पण सिन्हा, बादशा आलमगीर, अरिजीत चक्रवर्ती, रेजाउल चौधरी और परवाज खान के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में आयोजित आंदोलन में संबंधित पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। इसी आधार पर उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की गई है।

वहीं, महासचिव बापिरुल मंडल तथा सचिव पद पर कार्यरत साइनुर रेबा, दाबिश इस्तियाक और चंद्रशेखर गांगुली के खिलाफ भी निलंबन का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी एहसान अहमद खान तथा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस नेता रोहन मित्र ने निलंबित नेताओं का समर्थन किया है। उन्होंने नेतृत्व से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उनका कहना है कि लंबे समय से प्रतिकूल परिस्थितियों में संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं को उनकी अनुपस्थिति का कारण जाने बिना सामूहिक रूप से निलंबित करना उचित नहीं है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने कृषि भवन से कदीमी मस्जिद को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया

नई दिल्ली,एजेंसी। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने कृषि भवन से 'कदीमी मस्जिद' को हटाए जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा कि मस्जिद सार्वजनिक संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं है और इससे सरकार की पक्षपाती और सांप्रदायिक मानसिकता उजागर होती है।

मलिक मोतसिम खान ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'सरकार का यह दावा कि एक सदी पुरानी मस्जिद सार्वजनिक संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं है, एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है- वह कौन सा नियम है जो सरकारी परिसरों में किसी भी धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना की सुविधा पर रोक लगाता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, न कि लंबे समय से स्थापित पूजा स्थल को हटाने के लिए इसका उपयोग करना। केंद्र को अपने रुख के पीछे का कानूनी आधार स्पष्ट करना चाहिए, यह बताना चाहिए कि मस्जिद के इतिहास और लंबे समय से हो रहे इसके इस्तेमाल को किस तरह मान्यता दी गयी है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक मामला अदालत में है, तब तक कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिसे बाद में बदला न जा सके। उन्होंने कहा कि 'कदीमी मस्जिद' कृषि भवन परिसर के बनने से पहले से मौजूद है। असल बात यह है कि सरकारी दफ्तर 'कदीमी



मस्जिद' के आस-पास बनाए गए थे, न कि मस्जिद ने किसी पहले से मौजूद दफ्तर परिसर पर कब्जा किया था। वर्ष 1970 में मस्जिद के लिए जारी वक्फ अधिसूचना और 1940 का वह समझौता, जिसमें नमाज़ के लिए इसके इस्तेमाल को मान्यता दी गई थी- ये ऐसे मामले हैं जिन पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। सरकार इस इतिहास को महत्वहीन नहीं मान सकती और न ही किसी पुनर्विकास परियोजना के लिए मस्जिद के लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक उपयोग को एकतरफा तरीके से खत्म कर सकती है। खान ने कहा, 'दशकों से केंद्रीय सचिवालय के मुस्लिम कर्मचारी और आगंतुक इबादत के लिए इस नजदीकी इबादतगाह पर निर्भर रहे हैं। सरकार को यह मौलिक अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। क्या अन्य सार्वजनिक और सरकारी परिवेशों में भी धार्मिक प्रथाओं और प्रतीकों को जगह नहीं दी जा रही है? क्या यह सच नहीं है कि पूरे भारत में सार्वजनिक कार्यक्रमों, पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों में धार्मिक प्रथाओं, प्रतीकों, मूर्तियों और अनुष्ठानों (जैसे भूमि पूजन, हवन और धार्मिक स्थलों) को नियमित रूप से शामिल किया जाता है? सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास कानून के दायरे में होना चाहिए और इसमें मस्जिद का इस्तेमाल करने वालों के अधिकारों और चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। खान के मुताबिक मस्जिद समिति ने स्पष्ट किया है कि वह इस परियोजना को रोकना नहीं चाहती है; बल्कि सरकार को अपने प्रस्तावित प्रोजेक्ट में इस मौजूदा प्रार्थना स्थल की सुरक्षा और उसे शामिल करने के लिए लचीलेपन का प्रदर्शन करना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह न्याय के सभी मानदंडों का पालन करे।

राहुल अपनी राजनीतिक विफलताओं का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं: अनुराग

हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी राजनीतिक विफलताओं और संगठनात्मक कमजोरियों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनावी पराजय को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर देश में भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को पहले ही नकार चुकी है, लेकिन पार्टी अपनी हार से सबक लेने के बजाय बेबुनियाद आरोप लगाने में जुटी है।

अनुराग ठाकुर बुधवार को भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के तहत हमीरपुर में आयोजित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार और केरल सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं। यदि कांग्रेस ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चुनाव परिणामों के आधार पर केरल के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देंगे? कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उसके आरोप सही हैं या फिर कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों को मिला चुनावी जनादेश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा उसके छात्र संगठन की चुनावी पराजयों से भी लगाया जा सकता है। पंजाब विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक कांग्रेस का छात्र संगठन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक असफलताओं और संगठनात्मक कमजोरियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय भाजपा पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की रैली पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने के दावे किए गए, लेकिन वास्तविक उपस्थिति दावों के अनुरूप नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर अनावश्यक सवाल खड़े कर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस की इस राजनीति का तथ्यों के साथ जनता के बीच जवाब दें। सम्मेलन के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुमार पैलेस से गांधी चौक तक विशाल पथ यात्रा निकाली।

अमित शाह के दौरे से पहले दून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, वीवीआईपी मार्ग और कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन प्रतिबंधित

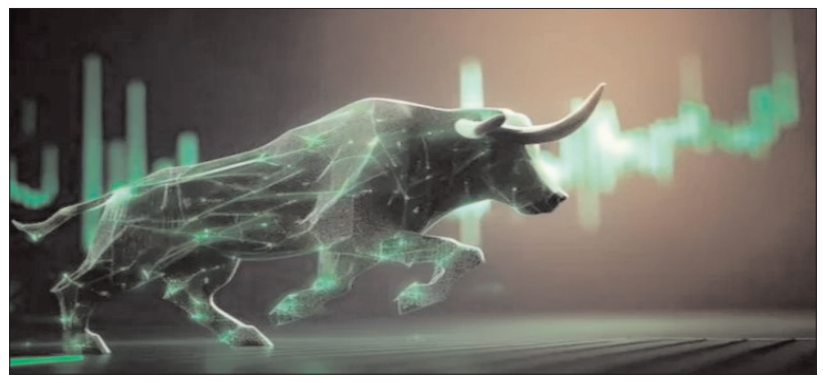
देहरादून,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छह नवंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वीवीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को बुधवार को पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रीफ किया। अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचने, सतर्कता बरतने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

अमित शाह छह नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से आयोजित पदयात्रा और जनसभा में शामिल होंगे। इसके अलावा वह पुलिस लाइन में में आयोजित होने वाली अलंकरण परेड कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भाजपा ने परेड ग्राउंड की जनसभा में 25 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिसकर्मियों को ड्यूटी शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचने और संबंधित प्रभारी अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उन्हें अपने ड्यूटी स्थल और आसपास के क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण करने को भी कहा गया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र और ड्यूटी कार्ड साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों को सादे कपड़ों और वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके ड्यूटी कार्ड की जांच करने को कहा गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों को अपना निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। केवल अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों को निर्धारित जांच एवं तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। गृह मंत्री से मिलने वाले व्यक्तियों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाएगी। पूर्व में अधिकृत लोगों को ही एंटी-सबोटाज जांच के बाद कार्यक्रम स्थल में प्रवेश मिलेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकासी के निर्धारित बिंदुओं पर प्रत्येक व्यक्ति की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग पर लोगों के अनावश्यक रूप से खड़े होने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीड़ के एक साथ बाहर निकलने से भगदड़ की आशंका को देखते हुए निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। पुलिसकर्मियों को लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को संयमित तरीके से बाहर निकालने और भीड़ पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

लगातार पांचवे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों को 5.83 लाख करोड़ से अधिक का मुनाफा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार आज लगातार पांचवें कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। बाजार में आज चौतरफा मजबूती का माहौल बना रहा, जिसके चलते दिग्गज शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जम कर खरीदारी हुई। इस चौतरफा लिवाली के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मुख्य सूचकांक दिन के ऊपरी स्तर (डे-हाई) के बेहद करीब बंद होने में सफल रहे। बाजार की इस तेजी के कारण आज निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। आज के कारोबार के दौरान शुरुआत में मामूली सुस्ती देखने को मिली, लेकिन जैसे ही वैश्विक बाजारों से सकारात्मक रुख आया, वैसे ही खरीदार पूरी तरह हावी हो गए। हालांकि सुबह दस बजे के बाद मुनाफावसूली के चक्कर में बिकवाली का दबाव भी बना, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद एक बार फिर लिवाली शुरू हो गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.50 प्रतिशत और निफ्टी 0.63 प्रतिशत की जोरदार मजबूती के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 64.74 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,853.11 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिसके कारण यह सूचकांक 478.19 अंक यानी 0.62 प्रतिशत उछल कर 77,396.04 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद मुनाफावसूली शुरू हो जाने के कारण यह सूचकांक ऊपरी स्तर से 791.19 अंक फिसल कर 313 अंक की गिरावट के साथ 76,604.85 अंक के निचले स्तर तक भी आया।

इसके बाद बाजार में मेटल, रियल्टी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में चौतरफा खरीदारी



शुरू हो गई। खासकर, दिन के अंतिम सत्र में खरीदारों ने लिवाली काफी तेज कर दी, जिससे सेंसेक्स निचले स्तर से 696.55 अंक की रिकवरी दिखाते हुए 383.55 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,301.40 अंक के स्तर पर पहुंच कर लगातार पांचवे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स की ही तरह एनएसई के निफ्टी ने आज 68.60 अंक यानी 0.29 प्रतिशत टूट कर 23,742.25 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही एफएमसीजी, फाइनेंस और ऑटो जैसी दिग्गज कंपनियों में शुरू हुई जोरदार लिवाली के चलते इस सूचकांक की चाल ने रफ्तार पकड़ ली। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी शुरुआती कारोबार में ही 23,946.35 अंक के स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने पर यह सूचकांक अपनी सारी बढ़त गंवा कर 114.70 अंक की कमजोरी के साथ 23,696.15 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद खरीदार पूरी तरह एक्टिव होकर लिवाली करने में जुट गए। चौतरफा लिवाली के सपोर्ट से निफ्टी तेजी से आगे बढ़ा। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी निचले स्तर से 264.45 अंक उछल कर दो सितंबर के बाद पहली बार क्लोजिंग बेसिस पर 23,900 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुए 149.75 अंक यानी 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,960.60 अंक के डे-हाई पर ही बंद हुआ। आज दिनभर के कारोबार के दौरान मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा चमक नजर आई, जहां दोनों इंडेक्स करीब 3-3 प्रतिशत की बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में डेढ़ प्रतिशत और ऑटो इंडेक्स में भी 1 प्रतिशत से अधिक की मजबूती दर्ज की गई। दूसरी ओर, आईटी सेक्टर के शेयरों में आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके चलते निफ्टी का आईटी इंडेक्स 1.50 प्रतिशत टूट कर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट और सेक्टोरल फ्रंट पर आज ज्यादातर इंडेक्स दबाव से पूरी तरह उबर कर बढ़त बनाने में कामयाब रहे। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में आज लगातार मजबूती बनी रही। निफ्टी

दिल्ली में 6-7 नवंबर को भव्य दीपावली उत्सव का आयोजन : कपिल मिश्रा

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार इस वर्ष दीपावली को राजधानी के सबसे भव्य और यादगार उत्सवों में शामिल करने जा रही है। 'दिल्ली की दिवाली' के अंतर्गत 6 और 7 नवंबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में भव्य दीपावली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6 नवंबर को शाम 6 बजे करेंगी। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होने वाला यह उत्सव दिल्लीवासियों के लिए सांस्कृतिक उल्लास, भक्ति और सामुदायिक सहभागिता का विशेष अवसर बनेगा।

दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को नौ शामनाथ मार्ग पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'दिल्ली की दिवाली' का उद्देश्य राजधानी में उत्सव की सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक एकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कनॉट प्लेस सहित दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर धरने-प्रदर्शनों के माध्यम से नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ऐसे माहौल में ऊर्जा और उत्साह का संचार करने तथा बाजारों में सकारात्मकता और रौनक बढ़ाने के उद्देश्य से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को इस आयोजन के केंद्र के रूप में चुना गया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी मार्केट एसोसिएशनों और आरडब्लूए के साथ मिलकर दीपावली उत्सव आयोजित कर रही है। दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में भी सरकार के सहयोग से उत्सव होंगे। उन्होंने बताया कि 'दिल्ली की



दिवाली' में ड्रोन शो के माध्यम से प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गणेश-लक्ष्मी जी की महाआरती भी विशेष आकर्षण होगी। सेंट्रल पार्क दीपों की रोशनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्सवी माहौल से जगमगाएगा। 7 नवंबर को भजन क्लबिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भक्ति और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली की दिवाली को नागरिकों की रचनात्मकता और सहभागिता से जोड़ने के लिए तीन विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें आरडब्लूए रंगोली, शूट 'एन शाइन और रील इट शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिल्ली की आरडब्लूए, युवाओं, रचनात्मक प्रतिभाओं और नागरिकों को अपनी कला, विचारों एवं उत्सव की झलक साझा करने का अवसर मिलेगा। आरडब्लूए रंगोली प्रतियोगिता के अंतर्गत दिल्ली की आरडब्लूए अपनी रंगोली कला और रचनात्मक सजावट के माध्यम से दिवाली की खुशियां, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता प्रदर्शित कर सकेंगी। इस प्रतियोगिता में गोल्डन दीया पुरस्कार के तहत 71,000 रुपये दो सिल्वर दीया पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 41,000 रुपये तीन ब्रॉन्ज दीया पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 21,000 रुपये तथा 25 विशेष पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 11,000 प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभागी 45 सेकंड तक की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। गोल्डन लेंस पुरस्कार के विजेता को 1,51,000 रुपयए दो सिल्वर लेंस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 1,01,000 रुपये तथा तीन ब्रॉन्ज लेंस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। रील इट प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी मौलिक फोटो के जरिए दिल्ली की दिवाली, उत्सव की खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता में गोल्डन फ्रेम पुरस्कार के तहत 1,01,000 रुपये दो सिल्वर फ्रेम पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 51,000 रुपये तथा तीन ब्रॉन्ज फ्रेम पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तीनों प्रतियोगिताओं के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्सव एवं सजावट, दिल्ली की विरासत, सामुदायिक एकता और सद्भावना के कार्य जैसे विषय सुझाए गए हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां 6 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जमा की जा सकती हैं। प्रतियोगिता संबंधी विस्तृत जानकारी दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @delhitourism_official पर उपलब्ध है।कपिल मिश्रा ने दिल्लीवासियों और राजधानी में आने वाले सभी लोगों से अपील की कि वे 'दिल्ली की दिवाली' के इस भव्य उत्सव में पूरे उत्साह के साथ शामिल हों। उन्होंने कहा कि सभी दिल्लीवासी 6 और 7 नवंबर को शाम के समय कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क पहुंचें और मिलकर पूरे जोश, उमंग और उल्लास के साथ दीपावली मनाएं।

धनतेरस के पहले सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 270 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। माना जा रहा है कि सोने के भाव में धनतेरस और दिवाली की वजह से तेजी का ये माहौल बना है। दूसरी ओर चांदी के भाव में आज लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुरुआती कारोबार में आज भी ये चमकीली धातु सोमवार के भाव पर ही बिक रही है।

भाव में बदलाव आने के कारण देश के अलग-अलग सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम के पुराने स्तर पर ही बिक



रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)